



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]
No. 166]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 2, 2003/आषाढ़ 11, 1925
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 2, 2003/ASADHA 11, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क निदेशालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2003

विषय : रूस, यूक्रेन तथा कोरिया गणराज्य से इंडक्शन हार्डन्ड फोर्ज्ड स्टील रोल्ल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच—अंतिम जांच परिणाम।

सं. 14/3/2002-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियम 1995 को ध्यान में रखते हुए:

क. प्रक्रिया

1. जांच के संबंधी में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:-

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी को (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है), उपरोक्त नियमों के तहत, मै0 गोंटरमैन - पाइपर (भारत) लि0 (जीपीए), पश्चिम बंगाल (जिसे इसके बाद याचिकाकर्ता कहा जाएगा) द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें रूस, यूक्रेन तथा कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित इंडक्शन हार्डन्ड फोर्ज्ड रोल्ल (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा जाएगा) के पाटन का आरोप लगाया गया है। मै0 हेवी इंजीनियरिंग कार्पो (एचईसी) राँची द्वारा भी याचिका का समर्थन किया गया है।

- (ii) प्राधिकारी ने उक्त नियमों के उपनियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही से पहले भारत में स्थित रूस, यूक्रेन तथा कोरिया गणराज्य के दूतावासों को याचिकाकर्ता द्वारा वायरा की गई याचिका की प्राप्ति के संबंध में सूचित किया।
- (iii) प्राधिकारी ने उपलब्ध जानकारी तथा तथ्यों के आधार पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरू करने का निर्णय लिया।
- (iv) प्राधिकारी ने दिनांक 27 अगस्त, 2002 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, अधिवारण में प्रकाशित किया गया जिसके द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं, जिन्हें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, की अनुसूची I के शीर्ष 8455 के तहत वर्गीकृत किया गया है, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू की गई।
- (v) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी जांच के संबंध में प्रारंभिक जांच निष्कर्षों को 11/03/2002 को अधिसूचित किया तथा हितबद्ध पार्टियों से उसके प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
- (vi) प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम की एक-एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों तथा भारत में स्थित सभी संबद्ध देशों के दूतावासों को अग्रेषित की तथा उनसे अनुरोध किया कि वे अपने देश के उत्पादकों और निर्यातकों को, प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रकाशन से 40 दिनों के भीतर अपने विचार, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने की सलाह दें।
- (vii) प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति नई दिल्ली स्थित रूस, यूक्रेन तथा कोरिया गणराज्य के दूतावासों को भी इस अनुरोध के साथ भेजी थी कि निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों को प्रारंभिक निष्कर्षों पर अपने-अपने विचार उपर्युक्त (v) और (vi) में दी गई समय सीमा के भीतर भेजने की सलाह दी जाए।
- (viii) प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों को अपने विचार 11 फरवरी 2003 को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। अपने विचार प्रस्तुत करने के बाद प्राधिकारी ने जांच निष्कर्षों (निष्कर्ष) तैयार करवाए कि वे हैं।

वाली सभी पार्टियों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित में दर्ज कराने का भी अनुरोध किया गया है। पार्टियों को प्रतिपक्षी पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियाँ लेने और उसका खंडन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने की सुलाह दी गई थी।

(ix) प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों को विभिन्न पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों वाली सार्वजनिक फाइल उनके अनुरोध पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई थी।

(x) प्रारंभिक निष्कर्षों की घोषणा से पहले हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों, जिन्हें पहले अधिसूचित किए गए प्रारंभिक निष्कर्षों में प्रकाशित किया गया है, को संक्षिप्तता के कारण इसमें दोहराया नहीं गया है। प्रत्येक हितबद्ध पार्टी द्वारा बाद में दिए गए तर्कों पर इन निष्कर्षों में उचित दृष्टि से विचार किया गया है।

(xi) उपरोक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए विचारित अनिवार्य तथ्यों/आधार को ज्ञात हितबद्ध पार्टियों के समक्ष प्रकट किया गया तथा इस विषय में उनके द्वारा दी गई टिप्पणियों पर इन निष्कर्षों में विचार किया गया है।

(xii) जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2001 से 30 जून, 2002 (पंद्रह महीने) तक मानी गई है।

(xiii) इस अधिसूचना में *** चिह्न से हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना प्रदर्शित होती है और नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी ने इसे गोपनीय ही माना है।

ख. याचिकाकर्ताओं, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार तथा प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच।

(i) विचाराधीन उत्पाद इंडक्शन हार्डनड फोर्ज्ड स्टील रोल्ल्स है, जिन्हें फोर्ज्ड सी आर एम (कोल्ड रोलिंग मिल्स) रोल्ल्स (300 मि.मी. व्यास से अधिक) के नाम से भी जाना जाता है। परिष्कृत संरचना, पतले गेज तथा उच्च यांत्रिक

विशेषताओं वाले ये कोल्ड रोल्ड कॉयल निम्नलिखित के लिए/द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं:-

- (क) गैल्वनाइजिंग लाइन जिसमें कोल्ड रोल्ड कॉयल पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है तथा इसका उपयोग भवनों के लिए छत की शीटों के रूप में होता है ।
- (ख) उपकरण विनिर्माताओं (ओइएम) जैसे कार बॉडीज, स्कूटर, बसों, आटो, फ्रिजों, वाशिंग मशीन, बर्तनों, सिगरेट फॉयलों तथा साइकिलें, इत्यादि ।
- (ii) फोर्ज्ड रोल मूल रूप से निर्वात गैसरहित मिश्र धातु से बनाए जाते हैं तथा द्रवचालित प्रेस में गढ़े जाते हैं । आंतरिक तनाव को हटाने तथा गढ़ने की प्रक्रिया के दौरान कणों के परिमार्जन के लिए फोर्जिंग की जाती है । उसके बाद रोल को वांछित माइक्रोस्ट्रक्चर के अनुसार गोलाकार बनाया जाता है । मशीनिंग के बाद रोल को इंडक्शन द्वारा कठोर बनाया जाता है तथा उसे अधिकतम कठोरता प्रदान करने के लिए 'नाइट्रोजन क्वेचिंग' भी की जाती है । फोर्ज्ड रोल्य की उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर तथा अंतिम मशीनिंग के बाद उपभोक्ता को सौंपने से पहले, अल्ट्रासॉनिक उपकरणों तथा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रयोग में आने वाले अन्य उपकरणों से रोलों की जांच की जाती है।
- (iii) फोर्ज्ड रोलों का उत्पादन कई आकारों में किया जाता है । तथापि, वर्तमान याचिका में 300 मि.मी. के आकार से कम के फोर्ज्ड रोल शामिल नहीं हैं । फोर्ज्ड रोल 'वर्करोल' या 'बैक अप रोल' हो सकते हैं । वर्क रोल और बैक अप रोल की कीमतों में काफी अंतर हो सकता है ।
- (iv) फोर्ज्ड रोल को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 84 के सीमाशुल्क उपशीर्ष सं० 8455.30.00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है ।

2. सेल द्वारा किए गए निवेदन:

- i) घरेलू उद्योग 600 मि.मी. व्यास से अधिक के फोर्ज्ड रोलों का उत्पादन नहीं करता है।
- ii) वर्तमान याचिका केवल इंडक्शन हार्डन्ड फोर्ज्ड रोल्स के विरुद्ध दायर की गई है। रोल कई प्रकार के होते हैं, जैसे वर्क रोल्स, बैक अप रोल्स इत्यादि। याचिकाकर्ता इस प्रकार के रोलों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं चाहते हैं, जबकि प्रारंभिक निष्कर्षों में इन पर भी पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। इन जैसे अन्य प्रकार के रोलों की लागत तथा कीमत संरचना काफी भिन्न होती है।
- iii) याचिकाकर्ता ने फोर्ज्ड रोलों के विनिर्माण तथा उनके गुण-धर्म तथा उपयोग के संबंध में केवल एक विवरण दिया है। अतः वर्तमान याचिका, 300 मि.मी. से अधिक तथा 600 मि.मी. से कम व्यास वाले फोर्ज्ड रोल्स तक सीमित है, जो याचिकाकर्ता की उत्पादन क्षमता के भीतर है। इस निवेदन के अनुसार प्रारंभिक निष्कर्षों द्वारा 300 मि.मी. व्यास से ऊपर के सभी रोलों पर शुल्क लगाया जाना गलत है तथा समर्थन योग्य नहीं है तथा इन्हें बंद कर देना/हटा लेना चाहिए। इसी प्रकार 300 मि.मी. से अधिक और 600 मि.मी. से कम के इंडक्शन हार्डन्ड फोर्ज्ड रोल्स पर, जो एकमात्र विचाराधीन उत्पाद है, के अलावा किसी अन्य प्रकार के रोलों पर किसी शुल्क का प्रस्ताव अथवा रोपण नहीं किया जा सकता।
- iv) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत 8455.30.00 उपशीर्ष के अध्याय में 'रोलिंग मिलों के लिए रोल्स' शामिल हैं, इसलिए जब तक स्पष्ट न किया जाए, तब यह उन सभी रोलों को, जो जांचाधीन संबंधित उत्पाद नहीं हैं के साथ-साथ हर प्रकार के रोलों को शामिल करेगा।

सेल के प्रकाशन विवरण के बाद किए गए निवेदन

- v) यह सराहनीय है कि प्राधिकारी संबद्ध वस्तुओं को (300-600 मि.मी. व्यास) तक सीमित रखने के लिए सहमत हो गए हैं। पुनः निवेदन किया जाता है कि जो उत्पाद जांच के अधीन नहीं हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से वर्तमान जाँचों को क्षेत्र से अलग कर दिया जाना चाहिए।

3. प्राधिकारी द्वारा जांच

:इसकी प्रा एकी प्राइ नर्स

- (i) प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क के अंतर्गत फोर्ज्ड रोल्ल्स (300 व्यास के ऊपर के आकार वाले) शामिल हैं। आगे, याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई याचिका में, वर्क रोल्ल्स तथा बैक रोल्ल्स शामिल हैं। वास्तव में, याचिकाकर्ता द्वारा विचार की जा रही अनियमित कीमत में वर्क रोल्ल्स तथा बैक अप रोल्ल्स शामिल थे। वर्क रोल्ल्स तथा बैक रोल्ल्स इंडक्शन हार्डनड फोर्ज्ड रोल्ल्स भी होते हैं। दोनों रोल्ल्स के बीच एकमात्र अंतर उनका विशिष्ट अंतिम उपयोग है। जहाँ एक प्रकार के रोल को स्टील रोलिंग के लिए सीधे प्रयोग में लाया जा सकता है, वहीं दूसरे प्रकार का रोल अप्रत्यक्ष रूप से स्टील रोलिंग में प्रयुक्त हो सकता है। याचिकाकर्ता ने, वास्तव में, विशेष तौर पर कहा था कि फोर्ज्ड रोल, वर्क रोल अथवा बैक अप रोल हो सकते हैं। केवल लोगत और कीमत से अंतर होने से वे भिन्न उत्पाद नहीं हो जाते हैं।

- (ii) प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता 300 मि.मी. से 605 मि.मी. तक व्यास के आकार के इंडक्शन हार्डनड फोर्ज्ड रोल्ल्स का उत्पादन कर सकता है। यह स्थिति याचिकाकर्ता के उत्पादन सुविधाओं का निरीक्षण करते समय भी सही पाई गई थी। याचिकाकर्ता ने 605 मि.मी. के संबद्ध माल की आपूर्ति के लिए बोकारो स्टील प्लांट द्वारा दिए गए आर्डर की प्रतियों का उत्पादन किया है।

- (iii) उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के 605 मि.मी. तक के आकार तक सीमित करते हैं। प्राधिकारी इंडक्शन हार्डनड फोर्ज्ड रोल्ल्स (300 मि.मी. से 605 मि.मी. व्यास का आकार) के रूप में उत्पाद के ब्यारे की पुष्टि करते हैं। जिसमें अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ बैक रोल्ल्स और वर्क रोल्ल्स समेत इंडक्शन हार्डनड फोर्ज्ड रोल्ल्स की सभी किस्में शामिल हैं।

ग. समान वस्तु

समान वस्तुओं का अर्थ वही वस्तु है जो मीटर में पादक की जा रही जांचाधीन वस्तु से मिलती जुलती या उसके सदृश्य है अथवा ऐसी वस्तु जो

यद्यपि सभी मामलों में समान नहीं हैं, के अभाव में जांचाधीन वस्तु के समान पुण्यधर्मों वाली वस्तु से है।

याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

(क) फोर्ज्ड स्टील रोलर्स का कोई व्यावहारिक प्रतिस्थापन नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित फोर्ज्ड स्टील रोल और संबद्ध देशों से निर्यातित माल में कोई भिन्नता नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित माल और संबद्ध देशों से आयातित माल तुलनीय हैं, जहां तक उनकी भौतिक विशेषताएं और रासायनिक बनावट, विनिर्माण प्रौद्योगिकी, निष्पादन, संयंत्र एवं उपकरण, विनिर्माण प्रक्रिया, कार्य एवं प्रयोगों, विमान एवं कीमत निर्धारण, उपभोक्ता की समझ का संबंध है, ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। फोर्ज्ड रोलर्स के उपभोक्ता इन दोनों का अदल-बदल कर प्रयोग कर रहे हैं। अतः याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित फोर्ज्ड रोलर्स और संबद्ध देशों से आयातित माल को पाटनरोधी नियमावली के अनुसार समान वस्तुएं समझा जाना चाहिए।

(ख) भारतीय उद्योग और संबद्ध देशों में विनिर्माताओं द्वारा अपनायी गयी प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा अपनायी गयी प्रौद्योगिकी संबद्ध देशों में फोर्ज्ड स्टील रोलर्स के विनिर्माताओं द्वारा अपनायी गयी प्रौद्योगिकी से तुलनीय है। तथापि, प्रत्येक विनिर्माता आवश्यकताओं और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर अपनी उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करता रहता है।

2. सेब द्वारा किए गए निवेदन:

प्रार्थनाएं निम्नलिखित हैं: (क) फोर्ज्ड स्टील रोलर्स - इंडोनेशिया

(i) शिकायतकर्ता घरेलू उत्पादक मैसर्स जीपीआई के पास संबद्ध पण्य वस्तु के उत्पादन की सुविधा नहीं है। उसके पास अपने उत्पादन इकाई में शिलिका निर्माण और ढलाई की सुविधा नहीं है। ढलाई सुविधा के अभाव में जी पी आई को संबद्ध पण्य वस्तु आई एच एफ

रोल्स का घरेलू उत्पादक नहीं कहा जा सकता है। सर्व-सम्मति से यह दावा किया जाता है कि मैसर्स जी पी आई अन्य स्रोतों से कोरे रोल्स की खरीद करता है और तत्पश्चात् उस पर उष्म अभिक्रिया और मशीनीनिंग जैसी प्रक्रिया की जाती है ताकि उनकी संबद्ध पण्य वस्तु इंडक्शन हार्डनेड फोर्ज्ड रोल्स नाम एवं किस्म में आपूर्ति की जा सके। इस प्रकार के उत्पादक को संबद्ध पण्य वस्तु का घरेलू उत्पादक नहीं कहा जा सकता है और इसकी कीमतों को उत्पाद के सामान्य मूल्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है। जी पी आई संबद्ध पण्य वस्तु का उत्पादक एवं विनिर्माता नहीं होने के कारण पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए वर्तमान याचिका प्रस्तुत करने और उसका समर्थन करने का हकदार भी नहीं है। मैसर्स जी पी आई ने उन स्रोतों का खुलासा नहीं किया है जहां से वह अपने यूनिट में प्रसंस्करण के लिए कोरे रोलों की प्राप्ति कर रहा है। वह संभवतः इनका आयात कर रही है। इस प्रकार से तथ्यों को छुपाना गलत है और इससे शिकायत रद्द हो सकती है।

- (ii) इंडक्शन हार्डनेड फोर्ज्ड रोल्स की विनिर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण हैं:-

इस्पात निर्माण एवं शिलिका निर्माण, पुनः ऊर्जा देना और ढलाई करना, सामान्यीकरण (ऊर्जा अभिक्रिया) - स्फेरोइडाइजिंग (एनीलिंग), टेम्परिंग इंडक्शन हार्डनिंग एवं टेम्परिंग। परीक्षण इत्यादि के अलावा, प्रूफ मशीनिंग एवं फाइनल मशीनिंग।

- (iii) घरेलू उद्योग में उपलब्ध सुविधाएं (सेल की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार):

जीपीआई - उनके पास केवल ऊर्जा अभिक्रिया एवं मशीनिंग सुविधाएं हैं। उनके पास परिष्कृत आई एच फोर्ज्ड रोल का निर्माण करने के लिए निविष्टि सामग्री के रूप में अपेक्षित कोरे रोलों का निर्माण करने के लिए शिलिका निर्माण एवं ढलाई प्रैस नहीं है। (जैसाकि विनिर्माण के लिए उनके पास उपलब्ध सुविधाओं के बारे में सेल की टिप्पणि के साथ जी पी आई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से निष्कर्ष निकाला जा

सकता है) यह भी ज्ञात है कि वे अपने सादे रोलों की खरीद घरेलू/आयात स्रोतों से करते हैं। इसलिए उनकी कीमतें उन विनिर्माताओं से अधिक होनी चाहिए जो विनिर्माता स्वयं सादे रोलों का विनिर्माण करते हैं।

एचईसी - उनके पास सादे रोलों का निर्माण करने, ऊर्जा अभिक्रिया सुविधाएं और मशीनिंग के लिए सभी अपेक्षित सुविधाएं हैं। बैकअप रोल्स के मामले में उनके पास केवल 25 टी तक के आकार की सुविधाएं हैं।

- iv) सेल की जानकारी के अनुसार, जी पी आई के पास 605 मि.मी. से अधिक के फोर्ज्ड रोल्स का निर्माण करने की सुविधाएं नहीं हैं। एच ई सी के पास केवल 25 टी (1300 व्यास) तक के आकारों के निर्माण करने की सुविधाएं हैं, किन्तु आंतरिक बाधाओं के कारण वे विनिर्माण एवं आपूर्ति करने के लिए सक्षम नहीं हैं जैसाकि 5 वर्षों तक भी उनकी आपूर्तियां लंबित रहने से स्पष्ट है। सेल को कई मामलों में लम्बित आर्डरों को एचईसी से अन्यत्र करने के लिए विवश होना पड़ा।
- v) विभिन्न पक्षकारों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के बीच न केवल उनकी विनिर्माण प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी एवं उपकरण में बल्कि विशिष्ट रूप से विनिर्माताओं/उत्पादकों द्वारा गारंटीशुदा निष्पादन के बीच महत्वपूर्ण अंतर है।

प्रकटीकरण विवरण के बाद किए गए अनुरोध

- (vi) सेल ने अपने पूर्ववर्ती अनुरोधों की पुनरावृत्ति की है।

3. निर्यातकों द्वारा किए गए अनुरोध:

मैसर्स एनकेएमजैड, उक्रेन

- i) भारतीय रोल्स विनिर्माताओं द्वारा प्रस्तुत विनिर्मित उत्पादों के विवरण का विश्लेषण करते हुए हमें यह मालूम होता है कि हमारे रॉलों के उत्पादन में इसकी उत्पादन पद्धति, प्रयुक्त उपकरण और सामग्री की रासायनिक बनावट की दृष्टि से काफी भिन्नता है।
- ii) सामग्री/प्रक्रिया विवरण के साथ कोल्ड रॉलिंग मिल विनिर्माण हेतु नेमी प्रक्रिया दी गयी है।
- iii) जे एस सी एन के एम जी के कोल्ड रॉलिंग मिल वर्क की उच्च गुणवत्ता की निम्नलिखित परिभाषा दी गयी है:
 - विशेष ऊर्जा का उपयोग-इस्पात प्रतिरोधक 60X 2 सी एम 0 सक्षम लैडल रिफाइनिंग एवं वैक्यूम डिगासिंग के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली धातु की व्यवस्था।
 - उन फोर्जिंग एवं इंडक्शन हार्डनिंग रॉलों की विशेष किस्मों का उपयोग जिनमें उच्च भौतिक एवं यांत्रिकी गुणधर्मों के स्तर वाले हार्डन्ड केस की पर्याप्त मोटाई होती है और अवशेष बल का उत्तम वितरण जो सेवा एवं उच्च गति से रॉलिंग की दशाओं में भी अपने टिकाऊपन सुनिश्चित करता है।

60X2 सी एम Φ स्टील से निर्मित कोल्ड रॉलिंग मिल वर्क रॉल 9X 2 एम Φ स्टील से निर्मित रॉलों से निम्न प्रकार से भिन्न होता है:-

- रासायनिक बनावट
- अधिक कठोरता और कठोर भेदन
- कम भुरभुरापन
- अत्यधिक ऊर्जा स्थिरता

रॉलों हेतु जिस धातु का इस्तेमाल किया जाता है उसकी विशेषताओं में भौतिक और यांत्रिक गुणधर्मों की उन्न जटिलता, सम्पूर्ण खण्ड में समदैशिकता है। भिन्न-भिन्न कोल्ड रॉलिंग मिल में 60X2 सी एम 0

स्टील के कार्य की प्रचालन अवधि भारतीय निर्माताओं द्वारा निर्मित 9x 2 एम 0 स्टील से बने रॉलों की तुलना में 1.3-1.7 गुना अधिक है। इसके अतिरिक्त हम यह बात नोट करना पसन्द करेंगे कि एनकेजैड के पास टीयूवी नॉर्ड कं0 का प्रमाण-पत्र है जो यह प्रमाणित करता है कि जे एस सी एन के एम जे ने विकास, डिजाईनिंग, विनिर्माण एवं धातुकर्मीय सुविधाओं की स्थापना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ 9001 के अनुरूप गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली लागू की है।

प्रकटीकरण विवरण के पश्चात् किए गए अनुरोध

iv) निर्यातकों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

4. प्राधिकारी द्वारा जांच

i) प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि रूस के एक निर्यातक ने यह सूचित किया है कि घरेलू उद्योग वह गुणवत्ता वाले माल का उत्पादन नहीं करता है जिसकी आवश्यकता भारतीय प्रयोक्ता उद्योग को है। उक्रेन के मैसर्स एन के एम जैड ने कहा है कि उनके रॉल उत्पादन पद्धति और सामग्री की रासायनिक बनावट की दृष्टि से भिन्न हैं। तथापि, प्रयोक्ता उद्योग द्वारा इस आशय का कोई दावा नहीं किया गया है और इस प्रकार के दावों का समर्थन भी नहीं किया गया है। यद्यपि यह दावा किया गया है कि प्रौद्योगिकी भिन्न रही है तथापि सामान्य मूल्य पर इस पहलू के प्रभाव का आंकलन नहीं किया जा सका है क्योंकि निर्यातकों ने पूर्णरूपेण सहयोग नहीं दिया है।

ii) जहां तक फोर्ज्ड सादे रॉलों के उत्पादन के लिए याचिकाकर्ता के पास सुविधाएं उपलब्ध न होने के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद इंडक्शन हार्डन्ड फोर्ज्ड रॉल्स है। सादे फोर्ज्ड, फोर्ज्ड रॉल्स के उत्पादन हेतु कच्ची सामग्री है। यद्यपि यह संभव है कि कुछेक उत्पादक सादे फोर्ज्ड और फोर्ज्ड रॉलों जो भिन्न-भिन्न और विशिष्ट उत्पाद का निर्माण करते हैं, का जितना भी उत्पादन करते हैं उसमें वे पूर्ण रूप से पिछड़े हुए हैं। यह कहा जा सकता है कि एक उत्पादक को फोर्ज्ड

रॉल्स का उत्पादक कहे जाने से पूर्व उसके पास फोर्ड ब्लैंक्स के उत्पादन के लिए भी सुविधाएं होनी चाहिएं ।

- iii) प्राधिकारी यह बात भी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा इस माल की आपूर्ति मैसर्स राउरकेला स्टील प्लॉट, कटनी, मैसर्स अग्रवाल मेटल्स, जयपुर, मैसर्स भूषण स्टील, मैसर्स हीरो साइकिल्स, मैसर्स इस्पात इंडस्ट्रीज लि०, मैसर्स आई टी डब्ल्यू सिग्नोटेक इंडिया लि०, मैसर्स जिंदल इन्डस्ट्रीज लि०, मैसर्स जिस्को (तारापुर), मैसर्स जिस्को (वासिंद), मैसर्स लायड्स स्टील, मैसर्स लीका इंजीनियरिंग, मैसर्स नेशनल स्टील्स, मैसर्स नेजोन स्ट्रिप्स, मैसर्स रूची स्ट्रिप्स एण्ड एलॉय लि०, मैसर्स श्री प्रीकोट्स, मैसर्स स्टेल्को गुजरात, मैसर्स सूर्या रोशनी, इंडियन मेल्टिंग एण्ड रिफाइनिंग कं० लि०, मैसर्स टिनप्लेट कं०, मैसर्स उत्तम स्टील, मैसर्स बल्लभ स्टील एवं मैसर्स वाल्जेन स्ट्रिप्स को की गयी है ।
- iv) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातित माल और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित माल नियम 2(घ) के अनुसार अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ है ।

घ. जांच की शुरुआत, आधार एवं घरेलू उद्योग

यह याचिका घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स गोटरमान-पैपर्स (इंडिया) लि०, पश्चिम बंगाल द्वारा दायर की गयी है । याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन में उनका हिस्सा 54.46% बनता है । मैसर्स हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (एचईसी) जिसका 45.55% का आधार है, याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका का समर्थन किया है । पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी उप नियम (क) के अंतर्गत दायर किए गए आवेदन के अनुसरण में तब तक कोई जांच-पड़ताल शुरू नहीं करेंगे जब तक कि वे समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रदत्त आवेदन के समर्थन अथवा विरोध की मात्रा की जांच के आधार पर यह निर्धारित नहीं कर लेते कि आवेदन घरेलू उद्योग अथवा उसकी ओर से किया गया है बशर्ते कि यदि आवेदन का समर्थन करने वाले

घरेलू उत्पादकों का हिस्सा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन का 25% से कम बनता है तो, कोई जांच नहीं की जाएगी। उप नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि आवेदन का समर्थन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया है जिनका संचयी उत्पादन आवेदन का समर्थन अथवा विरोध, जैसा भी मामला हो, व्यक्त करने वाले उस घरेलू उद्योग के हिस्से द्वारा, उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन का 50% से अधिक बनता है तो, आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से किया गया माना जाता है।

1. सेल द्वारा किए गए निवेदन:

- i) सेल की फोर्ज्ड रोल की वार्षिक आवश्यकता लगभग 4000 टन होती है, जैसाकि अनुबंध में बताया गया है। आई एच एफ रोल सेल के फोर्ज्ड रोल की कुल आवश्यकता का लगभग 25% होता है। सेल द्वारा वांछित फोर्ज्ड रोल 45 टन तक और 1610 एम एम व्यास तक के हैं। मैसर्स जी पी आई के पास सेल की कुल जरूरत की मात्रा के उत्पादन करने तथा उसे पूरा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- ii) सार्वजनिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा यह बात स्वीकार की गई थी कि वे ही ऐसी निजी कम्पनी हैं जिनके पास 300-605 एम एम व्यास के आकार के इंडक्शन हार्डनड रोल हेतु इंडक्शन हार्डनिंग तथा मशीनिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं और उनके पास स्टील मेकिंग तथा ब्लैंक मेकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मैसर्स टैयो, जमशेदपुर के संबंध में याचिकाकर्ता ने कहा है कि केवल इस उत्पाद की अन्तिम मशीनिंग अथवा फिनिशिंग को 'उत्पादन' नहीं कहा जा सकता है और कम्पनी के पास आई एच एफ रोल के उत्पादक के लिए अपेक्षित सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। याचिकाकर्ता के विचार का निष्कर्ष यह हो सकता है कि इसी प्रकार से चूंकि जीपीआई के पास केवल इंडक्शन हार्डनिंग तथा मशीनिंग सुविधाएं हैं और उनके पास स्टील मेकिंग तथा फोर्जिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं, अतः उन्हें आई एच फोर्ज्ड रोल का 'उत्पादक' नहीं माना जा सकता है। इस आधार पर जी पी ए को केवल एक व्यापारी ही माना जाए क्योंकि

उनके पास इंडक्शन हार्डण्ड फोर्ज्ड रोलस के उत्पादन हेतु आवश्यक स्टील मेकिंग सुविधा, प्रौद्योगिकी तथा विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है।

- iii) जी पी आई के पास इस माल के उत्पादन हेतु उत्पादन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उनके पास शिल्लिका निर्माण तथा फोर्जिंग सुविधाएं नहीं हैं। रोल के उत्पादन में महत्वपूर्ण कदम इस्पात निर्माण शिल्लिका निर्माण, रिहीटिंग, फोर्जिंग, नार्मलाइजिंग, स्फेरोडाइजिंग (एन्नीलिंग), टेम्परिंग, इंडक्शन हार्डनिंग टेम्परिंग, प्रूफ मशीनिंग तथा फाइनल मशीनिंग करना हैं। जी पी आई के पास ये सभी सुविधाएं नहीं हैं। जबकि एच ई सी के पास ये सुविधाएं उपलब्ध हैं लेकिन वे अपनी आन्तरिक समस्याओं की वजह से सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं।
- iv) याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई क्षमताएं अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होती हैं क्योंकि ये कम्पनियां सप्लाई नहीं कर पाई हैं।
- v) सेल की पूरी जरूरत को एचईसी और जीपीआई पूरा नहीं कर सके हैं।
- vi) चूंकि इस कम्पनी ने वाणिज्यिक उत्पादन केवल पिछले 2-3 वर्षों से ही आरंभ किया है, अतः वे क्षति का दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सम्पूर्ण विनिर्माण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और उन्होंने फाइनल प्रोसेसिंग सुविधाएं केवल पिछले दो वर्षों में ही सृजित की हैं।
- vii) उपरोक्त को देखते हुए, याचिकाकर्ता संबद्ध उत्पाद के उत्पादक नहीं हैं और वे पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु यह याचिका दर्ज कराने तथा इसका दावा रखने के पात्र नहीं हैं। याचिकाकर्ता अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा करके वे रोल उत्पादकों को भारतीय ग्राहक को न केवल क्वालिटी बल्कि उत्पादों/कीमतों पर बहुत ही कम विकल्प देकर उन्हें अनुचित तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे हैं।

2. यूक्रेन द्वारा किए गए निवेदन:

- (i) निवेदन है कि भारतीय बाजार को सप्लाई किए कोल्ड रोलिंग मिल वर्क रोल्स की कीमत एनकेएमजेड द्वारा घरेलू बाजार तथज्ञा सीआईएस देशों को सप्लाई किए गए ऐसे ही रोल्स की कीमत-स्तर पर है। हमारी सोच में याचिकाकर्ता नामतः प्राइवेट कम्पनी गोन्टरमैन-पीपर्स लि० औद्योगिक प्रमुखता की ओर से पेश नहीं होते हैं और वे ऐसे माल के कुल उत्पादन के 50% से अधिक उत्पादन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और दस्तावेज के अनुसार आयातक का दृष्टिकोण अप्रत्यापक है क्योंकि इसे केवल एक ही कम्पनी 'टिनप्लेट कं० ऑफ इण्डिया लि० द्वारा प्रस्तुत किया गया है लेकिन जे एस सी एनकेएमजेड उत्पाद के सेल, राउरकेला, बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट जैसे बड़े आयातकों की राय इस दस्तावेज में प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. प्राधिकारी द्वारा जांच:

- (i) प्राधिकारी यह बात नोट करता है कि यह जरूरी नहीं है कि याचिकाकर्ता आधारीक चरण से उत्पादन करें। इस बात को सिद्ध करने हेतु कोई ऐसा अकाट्य कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि फोर्ड ब्लैक के चरण से आरंभ उत्पादन को पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर उत्पादन क्यों नहीं माना जाता है। इसके अलावा, ऐसी कल्पना की गई प्रतीत होती है कि फोर्ड ब्लैकों के उत्पादन में प्रयास शामिल नहीं होते हैं। यह बात सिद्ध नहीं की गई है कि कम्पनी पर फोर्ड ब्लैकों की अपेक्षतया अधिक कीमत देने हेतु दबाव डाला गया है।
- (ii) प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग की परिभाषा अन्य बातों के साथ-साथ यह दी गई है 'का अर्थ सम्पूर्ण घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबंधित किसी कार्यकलाप में लगे हों...'। इस नियम-स्थिति के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं को घरेलू उद्योग का एक हिस्सा मान लिया जाए।

- (iii) उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी यह निर्णय देता है कि याचिकाकर्ता प्रासंगिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3)(क) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने हेतु मानदण्ड पूरा करते हैं। प्राधिकारी इन याचिकाकर्ता कम्पनियों को उपर्युक्त नियम 2 (ख) के आशय में घरेलू उद्योग मानता है।

ड. डिमिनिमस सीमा

संबद्ध देशों से आयात संख्या में होता बताया जाता है। किन्तु याचिकाकर्ता द्वारा गौण स्रोतों से एकत्रित जानकारी में यह बताया गया है कि आयात विभिन्न यूनिट संख्या जैसे संख्या, भार पी सी तथा मीटर में बताया जा रहा है। इसके अलावा, संख्याओं के मामले में एक बड़े आकार का फोर्ड सीआरएम रोल और छोटे आकार का सीआरएम रोल दो ही माने जाएंगे जबकि इन दोनों का मूल्य बिल्कुल अलग-अलग होगा। जहां तक इस बात का पता लगाने की बात है कि क्या जांच-अवधि के दौरान संबद्ध देशों से किए गए आयात डिमिनिमस स्तर से अधिक रहे हैं, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत गौण स्रोतों अर्थात् इन्फोड्राइव इण्डिया और नाजुक जानकारी का हवाला दिया जिन्हें जांच अवधि के दौरान प्रकाशित किया गया था। प्राधिकारी ने यह तय करने हेतु फोर्ड ब्लैकों के भारत स्वरूप आयात-मात्रा का मूल्यांकन किया है कि क्या किसी देश विशेष से किया गया आयात डिमिनिमस सीमा से अधिक रहा। तीन देशों के आयात आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं -

देश	मात्रा एम.टी.	% हिस्सा
रूस	*****	17.07
यूक्रेन	*****	23.9
कोरिया	*****	25.88

इस प्रकार प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जांच-अवधि के दौरान संबद्ध देशों से किए गए आयात डिमिनिमस सीमा से अधिक रहे हैं।

1. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत:

किसी वस्तु के सामान्य मूल्य का अर्थ है-

(क) सामान्य व्यापार में समान वस्तु के लिए तुलनात्मक कीमत जब वह निर्यातक देश अथवा क्षेत्र में खपत के लिए हो।

(ख) जब समान वस्तुओं की निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार में कोई बिक्री नहीं हो अथवा निर्यात देश अथवा क्षेत्र में किसी बाजार-स्थिति अथवा कम बिक्री मूल्य के कारण ऐसी बिक्रियों से उचित तुलना न हो सके तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से एक होगा -

(क) समान वस्तु की तुलनात्मक प्रतिनिधि कीमत जब उस वस्तु का निर्यात निर्यातक देश अथवा क्षेत्र से किसी समुचित तीसरे देश को हो, अथवा

(ख) उद्भव के देश में संबद्ध माल की उत्पादन लागत जिसमें उपधारा (6) के तहत बनाई गई नियमावली के अनुसार निर्धारित प्रशासनिक, बिक्री तथा सामान्य लागत और लाभ शामिल हों।

बशर्ते कि उस वस्तु के मामले में जिसका आयात उसके उद्भव के देश से इतर किसी ऐसे देश से हो जहां से उसे निर्यातक देश की मार्फत नौकान्तरित किया गया हो अथवा उस वस्तु का उत्पादन निर्यातक देश में नहीं हुआ हो अथवा निर्यातक देश में उसकी कोई भी तुलनात्मक कीमत नकहीं हो तो ऐसी स्थिति में उसके सामान्य मूल्य का निर्धारण उसके उद्भव के देश में उसकी कीमत के संदर्भ में होगा।

प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनाथ सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क (i)(ग) के अनुसार सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं ।

क. यूक्रेन द्वारा किए गए निवेदन

i) निर्यातक ने निवेदन किया है कि कोई व्यक्ति इस वक्तव्य से सहमत नहीं हो सकता है कि यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसकी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था हो । जैसा कि सामान्यतया मालूम है कि बाजार अर्थव्यवस्था श्रम के सामाजिक विभाजन के विकास, वस्तु उत्पादन तथा विनिमय पर आधारित होती है जो प्रतियोगिता कीमत निर्धारण तथा मांग एवं आपूर्ति वसूली के संचलन तथा आकार निर्माण में बाजार में मौजूद हो । प्रत्येक निजी वस्तु उत्पादक मुद्रा हेतु अपने माल की विनिमय-प्रक्रिया के दौरान मालूम करता है कि समाज के लिए उसका कितना श्रम आवश्यक है जो श्रम के सामाजिक विभाजन प्रणाली में लगाह और उसे सामाजिक स्वरूप किस स्तर तक प्राप्त हुआ है ।

ii) बाजार अर्थव्यवस्था के कुशल कार्यचालन में सम्पदा एवं आर्थिक प्रबंधन के विविध रूपों तथा एक सुविकसित अवस्थापना का पता चलता है । बाजार अर्थव्यवस्था में एक जटिल ढांचा होता है और इसमें निम्न प्रकार के बाजार शामिल होते हैं -

क. वस्तु एवं सेवा बाजार ।

ख. उत्पादन कारक बाजार ।

ग. वित्तीय एवं मुद्रा बाजार ।

iii) यूक्रेन में स्थापित आर्थिक स्थिति इन सभी जरूरतों को पूरा करती है । इस तथ्य की पड़ताल यूक्रेन के मौजूदा कानून से

होती है। उपर्युक्त संबंधों का संचालन सिविल कोड, श्रम कानून कोड, कीमत एवं कीमत-निर्धारण, सम्पत्ति, अनुचित प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण, उद्यमिता, यूक्रेन में उद्यमों से संबंधित यूक्रेन के कानूनों और यूक्रेनी तथा अन्तर्राष्ट्रीय किस्म के अनेक विनियामक एवं कानूनी अधिनियमों द्वारा किया जाता है।

- iv) जैसाकि हमने पहले ही ऊपर नोट कर लिया है, जेएससी एनकेएमजेड फोर्ज रोलिंग मिल रोल्स का उत्पादन पिछले 60 वर्षों से कर रहा है और उसे क्षेत्र में काफी लम्बा अनुभव प्राप्त है। स्वाभाविकतौर पर, हमारे पास रोल्स विनिर्माण हेतु समायोजित तकनालॉजी है और उसके निर्माण हेतु लागत भी कम है। गोंटरमैन पीपीर्स लि० ने फोर्ज रोलिंग मिल रोल्स का उत्पादन हाल के समय में आरंभ किया है और हमारी राय में वे भारतीय बाजार में रोल्स निर्माण हेतु लागत कम करने के तरीके से नहीं जिसके फलस्वरूप रोल्स की कीमत में गिरावट हो बल्कि पाटनरोधी जांच की सहायता से रूस, यूक्रेन तथा कोरिया के उद्यमों पर दबाव के प्रयास द्वारा प्रवेश करना चाहेंगे।

ख) रूस द्वारा किए गए निवेदन:

- (i) रूसी पक्षकार ने 'उरालमाश प्लांट' जे एस सी ने भारतीय पक्षकार द्वारा मांगे गए हर संभव आंकड़े व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए हैं जिनमें रोल विनिर्माण - कीमत के आंकड़े भी शामिल हैं। संयुक्त स्टॉक कम्पनी ने जानकारी निर्यातकों के लिए निर्धारित प्रश्नावली के प्रपत्र-7 में प्रस्तुत नहीं की है क्योंकि इस दस्तावेज की अन्तर्वस्तु स्पष्ट नहीं थी। इस तथ्य का अर्थ यह नहीं है कि संयुक्त स्टॉक कम्पनी ने उत्पादों की विनिर्माण - कीमत के आंकड़े पूर्णतया प्रस्तुत नहीं किए हैं। अतः ऐसी जानकारी प्रश्नावली के अन्य प्रपत्रों में प्रस्तुत की गई।

- (ii) प्रश्नावली से संलग्न जानकारी के अलावा, " उरालमैश प्लांट " जेएससी ने मांगे गए आंकड़े प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र सं० 7 को भरने और विनिर्माण-लागत संबंधी जानकारी सहित कुछ भी प्रार्थित जानकारी प्रस्तुत करने हेतु उसे तैयार करने के बारे में विस्तार से बताए जाने की आवश्यकता व्यक्त की ।
- (iii) भारतीय पक्षकार ने तय किया कि संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूरोपीय यूनियन के देशों की तुलना में रूस एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है । सन् 2002 के अन्त में रूस को उक्त देशों द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था के देश के रूप में मान्यता दी गई है और ऐसा विश्व व्यापार संगठन में उसके संबंध हेतु किया गया (रूस इस संगठन में डब्ल्यूटीओ के नौ सदस्य-देशों को शामिल करने की शर्तों से पूर्णतया सहमत हो गया और पन्द्रह देशों के साथ वार्ताएं सन् 2003 के वसन्त तक आरंभ कर ली जाएंगी) ।

ग) सेल द्वारा किए गए निवेदन:

- i) याचिकाकर्ताओं ने तथाकथित पाटन को साबित करने का कोई प्रयास नहीं किया है बल्कि इस दावे का सहारा लिया है कि तथाकथित निर्यातक देश गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाएं हैं । निर्यातक देश संबद्ध व्यापार के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाएं नहीं हैं । रूस को बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता पहले ही मिल गई है । ऐसा मान लेना गलत होगा कि रूस अथवा यूक्रेन गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है और उन पर पाटन शुल्क लगाए गए । जो धारणाएं याचिकाकर्ता मान रहे हैं वे पूर्णतया अतर्कसंगत हैं और इस तरह के अतर्कसंगत निष्कर्षों के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं लिया जा सकता है ।
- ii) आगे यह भी निवेदन है कि इंडक्शन हार्डण्ड फोर्ज्ड रोल्स मानक उत्पाद नहीं है । ये रोल मानक कीमत-तंत्र युक्त नहीं होती हैं और इनकी सप्लाय तथा खरीद वजन तथा विनिर्देशनों के आधार पर होती है और उनमें भी जरूरत तथा अन्तिम

प्रयोग के आधार पर एक रोल से दूसरे रोल की अलग-अलग होती हैं । तदनुसार, संबद्ध उत्पाद के संबंध में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रश्न का कोई आधार नहीं है ।

घ) याचिकाकर्ता द्वारा किए गए निवेदन:

i) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने रूस, यूक्रेन कोरिया जनवादी गणराज्य के निर्यातकों/उत्पादकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों का पता लगाने हेतु प्रश्नावलियां भेजी । किन्तु, कोरिया तथा यूक्रेन के किसी भी निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्तर नहीं भेजा । अतः याचिकाकर्ता का निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह इन देशों के संबंध में प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करें ।

ii) रूस के संबंध में निवेदन है कि निर्यातकों ने याचिकाकर्ता के इस दावे का खंडन नहीं किया है कि रूस एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है । याचिकाकर्ता ने दावा किया कि रूस उस नियमावली के आधार पर एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है जो इस प्रकार है - एक ऐसी परिकल्पना होगी कि वह देश एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का देश है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ अथवा जांच के पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान किसी डब्ल्यूटीओ सदस्य देश द्वारा ऐसा माना गया हो ।

स्पष्ट रूप से यदि किसी देश को किसी अन्य डब्ल्यू टी ओ सदस्य देश द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश माना गया हो तो उस देश को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश समझा जा सकता है । रूस को संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूरोपीय संघ द्वारा आमतौर पर अनेक जांच कार्यों में और पिछले तीन वर्षों की अवधि में विशेष रूप से (संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा) ढांचागत प्रतिबंधों के रूप गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना गया है । इसलिए, याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-1 के नियम 7 तथा 8 में प्रदत्त उपबंधों के अनुसार किया जाए ।

- iii) ऐसी स्थिति के चलते याचिकाकर्ता का निवेदन है कि उत्पादन-लागत अथवा घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के बयौरे प्रदान करने के मुद्दे की कोई प्रासंगिकता नहीं बनती, जहां तक रूस के बारे में सामान्य मूल्य-निर्धारण का संबंध है। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता का निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह रूस के संबंध में भी प्रारंभिक निष्कर्ष की पुष्टि करें

2. प्राधिकारी द्वारा जांच:

i) दक्षिण कोरिया तथा यूक्रेन

(क) सामान्य मूल्य

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दक्षिण कोरिया अथवा यूक्रेन के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर के रूप में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी ने इन देशों द्वारा आंकड़े और सहयोग नहीं दिए जाने पर याचिकाकर्ता द्वारा यथा उपलब्ध कराई गई सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर दक्षिण कोरिया तथा यूक्रेन के सभी उत्पादकों तथा निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। अतः नियम 6(8) के अन्तर्गत याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई उत्पादन-लागत में उचित समायोजन करके उसे दक्षिण कोरिया तथा यूक्रेन में संबद्ध माल के सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ संदर्भ बनाया गया है। दक्षिण कोरिया तथा यूक्रेन के संबंध में इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य ***** अमरीकी डालर प्रति एम टी है।

(ख) निर्यात कीमत

जांच की अवधि में संबद्ध माल की निर्यात कीमत के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी निर्यातक/आयातक से कोई सहयोग नहीं मिलने पर याचिकाकर्ता द्वारा निर्यात कीमत संसंबंधी जानकारी गौण स्रोतों से उपलब्ध कराई है। इसे देखते हुए प्राधिकारी का दिनांक 11 दिसंबर, 2001 के प्रारंभिक निष्कर्षों में इंगित विधि की पुष्टि करने का प्रस्ताव है। प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त अर्न्देशीय भाड़े, पत्तन व्यय, महासागरीय भाड़े और समुद्री व्यय के समायोजन पर विचार किया जाए। दक्षिण कोरिया के संबंध में उक्त समायोजन करने के पश्चात् निर्यात कीमत ***** अमरीकी डालर प्रति एम टी बैठती है। यूक्रेन के संबंध में समायोजन उसी स्तर पर किए गए जितने रूस के संबंध में किए गए थे। उक्त समायोजन के पश्चात् निर्यात कीमत ***** अमरीकी डालर प्रति एम टी आती है।

ii) रूस(क) सामान्य मूल्य

- (i) प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस के केवल एकमात्र निर्यातक/उत्पादक - मै0 उरामलैश प्लांट ने भारत को बेचे गए संबद्ध माल की घरेलू कीमत और निर्यात कीमत बताई है। प्रश्नावली के प्रति निर्यातकों का उत्तर अपूर्ण है। परिशिष्ट-I के तहत वांछित जानकारी भी वर्ष 2000 के

लिए दी गई है जबकि यह जांच-अवधि अर्थात् अप्रैल 2001 से जून, 2002 तक की अवधि के लिए होनी चाहिए थी। कंपनी ने प्राधिकारी को परिशिष्ट 7 उपलब्ध नहीं कराया है जिससे कि पता लग सके कि क्षमता, उत्पादन कितना है और प्रस्तुत परिशिष्टों का समाधान हो सके। फैक्ट्री लागत तथा लाभ संबंधी जानकारी भी अपूर्ण है क्योंकि विभिन्न लागत शीर्षकों के तहत कोई जानकारी नहीं दी गई है। निर्यातक ने अपना वित्तीय विवरण-पत्र अथवा अन्य विवरण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं

- (ii) अतः प्राधिकारी इस तथ्य को देखते हुए कि निर्यातक ने संबद्ध माल के उत्पादन लागत के आंकड़े पर्याप्त उपलब्ध नहीं कराए हैं। इससे प्राधिकारी व्यापार-परीक्षण का सामान्य तरीका लागू नहीं कर सके हैं और वे उपर्युक्त नियम 6(8) के अनुसार उचित समायोजन कर उत्पादन की तैयार की गई लागत के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा सामान्य मूल्य तय नहीं कर सके हैं। प्राधिकारी ने रूस के सभी निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य ***** अमरीकी डालर प्रति एम टी पर निर्धारित किया है।

(ख) निर्यात कीमत

प्राधिकारी ने संकेत दिया है कि सीआईएफ निर्यात कीमत का निर्धारण पैकेजिंग, अन्तर्देशीय भाड़े, भण्डारण, महासागरीय भाड़े, महासागरीय बीमा तथा प्रलेखन लागत के समायोजन जैसा कि जांच-अवधि के दौरान संबद्ध माल के संबंध में निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किया है, के आधार पर किया जाए। इसे देखते हुए प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि दिनांक 11 दिसंबर, 2001 के प्रारंभिक निष्कर्षों में इंगित विधि की पुष्टि की जाए। उक्त समायोजन किए जाने के पश्चात् निर्यात कीमत का निर्धारण***** अमरीकी डालर प्रति एम टी होता है।

3. पाटन मार्जिन:

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क(क) के अनुसार किसी वस्तु के संबंध में 'पाटन के मार्जिन' का अर्थ उसकी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के अंतर से है। पाटन मार्जिन नीचे दर्शाया गया है:-

देश	रूस(सभी निर्यातक एवं उत्पादक)	यूक्रेन (सभी निर्यातक एवं उत्पादक)	कोरिया (सभी निर्यातक एवं उत्पादक)
सामान्य मूल्य	****	****	****
निर्यात कीमत	****	****	****
पाटन मार्जिन %	79.65	67.51	11.06

च. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

क. याचिकाकर्ता के विचार:

1. याचिकाकर्ता ने कहा है कि विभिन्न कारणों चाहे वे सामूहिक हों तथा संचयी हों, से यह सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
2. याचिकाकर्ताओं ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी विस्तृत जानकारी प्रदान की है जिससे स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। इसके अलावा, पाटन के फलस्वरूप वास्तविक क्षति होने की भारी आशंका है। याचिकाकर्ताओं का निवेदन है कि घरेलू उद्योग को क्षति के कारकों का सारांश इस प्रकार है:-

3. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात में समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई है ।
4. भारत में संबद्ध वस्तु के कुल आयातों की दृष्टि से संबद्ध देशों से हुए आयात के बाजार हिस्से में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है
5. भारत में संबद्ध वस्तु की मांग/खपत के संबंध में संबद्ध देशों से हुए आयातों के हिस्से में महत्वपूर्ण ढंग से वृद्धि हुई है ।
6. घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले आर्थिक मापदण्ड:

यद्यपि घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और इसी प्रकार बिक्री में वृद्धि हुई । तथापि घरेलू उद्योग उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया । घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग अत्यधिक कम है और पाटित आयातों के कारण संबद्ध वस्तु को बेचने में सक्षम नहीं है ।

आयातों ने घरेलू उद्योग को उत्पाद को इसके उचित मूल्य से कम पर बेचने को बाध्य किया है, क्योंकि घरेलू उद्योग को समान कीमतें रखने के लिए बाध्य होना पड़ा है । इस प्रकार, आयातों से घरेलू उद्योग उत्पाद को घाटे पर बेचने को बाध्य हुआ है ।

7. आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम था जिसके चलते भारतीय बाजार में कीमत कटौती हुई है।
8. आयातित सामग्री का पहुंचमूल्य उत्पादन लागत तथा घरेलू उचित बिक्री कीमत के काफी कम है परिणामस्वरूप भारतीय बाजार में जबरदस्त कीमत ह्रास हुआ है ।
9. भारतीय बाजार में लगातार पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है ।

10. यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है तथापि उद्योग को अब भी घाटे उठाने पड़ रहे हैं ।

11. घरेलू उद्योग द्वारा उठाये गए वित्तीय घाटों के चलते नकद प्रवाह बुरी तरह प्रभावित हुआ है ।

12. घरेलू उद्योग नयी पूंजी जुटाने या नये निवेश की योजना बनाने में सक्षम नहीं है । वस्तुतः, याचिकाकर्ता को परियोजना के कार्यान्वयन को रोकना पड़ा था ।

13. पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि अत्यधिक है। भारी पाटन मार्जिन के कारण घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

14. अमरीकी डालर के रूप में शुल्क :

यद्यपि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहले ही अमरीकी डालर के रूप में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश कर दी है, फिर भी यह अनुरोध किया जाता है कि अंतिम शुल्क की सिफारिश भी केवल अमरीकी डालर के रूप में की जाए ताकि विनिमय दर में परिवर्तन के चलते संरक्षण के कारण अपवंचन न हो सके । तथापि, कृपया संदर्भ कीमत के रूप में शुल्क की सिफारिश की जाए जैसाकि प्रारंभिक जांच परिणाम में किया गया था ।

15. क्षति का संचयी मूल्यांकन

इस मामले में क्षति के संचयी मूल्यांकन के लिए बनाए गए नियमों के अंतर्गत उल्लिखित मापदंड भली-भांति पूरे होते हैं क्योंकि (क) प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है; (ख) प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा

से अधिक है ; तथा (ग) आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति के आलोक में आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित है ।

याचिकाकर्ता ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को पहले ही ब्यौरेवार जानकारी दी है जिससे स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई । इसके अलावा, पाटन के परिणामस्वरूप भारी वास्तविक क्षति का खतरा बना हुआ है । याचिकाकर्ता ने कहा है कि निम्नलिखित मापदंडों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति स्पष्ट होती है:-

- i) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों में समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई है ।
- ii) भारत में संबद्ध वस्तु के कुल आयातों में संबद्ध देशों से हुए आयात के बाजार हिस्से में महत्वपूर्ण ढंग से वृद्धि हुई है ।
- iii) भारत में संबद्ध वस्तु की मांग/खपत की दृष्टि से संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।

16. मांग की पूर्ति:

घरेलू उद्योग 300-605 मि.मी. व्यास आकार के इंडक्शन हार्डनेड फोर्ज्ड रॉल्स के संबंध में रक्षोपाय की मांग कर रहे हैं । घरेलू उद्योग इन आकारों के फोर्ज्ड रॉल्स बेच रहा है । घरेलू उद्योग निर्दिष्ट आकार की संबद्ध वस्तु का मांग को पूरा करने में सक्षम है । आगे यह भी बताया गया है कि मांग पूरा करना पाटनरोधी शुल्क लागू करने की पूर्वापेक्षा नहीं है । किसी मामले में, यदि भविष्य में कम आपूर्ति तथा ऊंची कीमतों की स्थिति होगी तो निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उस मामले में एक संदर्भ कीमत की सिफारिश की है। इन पक्षकारों द्वारा उचित कीमतों पर कभी भी आयात किया जा सकता है।

17. सेल (एसएआईएल) के लिए रॉल्स का महत्व

सेल का तर्क उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता को और अधिक प्रबल बनाता है ताकि सेल हर समय उत्पाद की उपलब्धता के प्रति आश्वस्त रहे । वस्तुतः, जब भी सेल को विदेशी उत्पादकों से समय पर आपूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जी पी आई ने उनकी सहायता की है तथा उन्हें आवश्यक महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री की आपूर्ति की है ।

18. सेल को फोर्ज्ड रोल की आपूर्ति:

जी पी आई के संबंध में सेल का यह तर्क कि वह समय पर सामग्री की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, गलत है । वस्तुतः जब भी सेल को आयातित माल की डिलीवरी प्राप्त नहीं हुई है, जी पी आई ने सेल की सहायता की है ।

19. एचईसी द्वारा निविदा में उद्धृत कम कीमतें

सेल को यह बात समझनी चाहिए कि विभिन्न निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा में उद्धृत कीमतें उन विभिन्न पक्षकारों के ध्यान में होती हैं जो निविदा में भाग ले रहे हैं । अन्य आपूर्तिकर्ताओं की मौजूदगी स्वतः ही उन कीमतों पर प्रभाव डालती है जिन्हें अन्य उत्पादक उद्धृत करते हैं । इस प्रकार, एच ई सी द्वारा उद्धृत कम कीमतों को बाजार में मौजूद अन्य आपूर्तिकर्ताओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए ।

20. एच ई सी का उत्पादन:

एच ई सी संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण कर रही है । सेल का यह आरोप कि एच ई सी संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है, वस्तुतः गलत है । यह अप्रासंगिक है कि यह कंपनी एक बी आई एफ आर कंपनी है । एक बी आई एफ आर कंपनी का यह अर्थ नहीं

है कि वो कंपनी उत्पादन नहीं कर रही है। जब तक कंपनी संबद्ध वस्तु का उत्पादन कर रही है वह पाटित आयातों से संरक्षण की मांग कर सकती है। पी आई बी के मामले में, यद्यपि याचिकाकर्ता एक बी आई एफ आर कंपनी है, तथापि पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता उचित कीमतों पर किसी आयात का विरोध नहीं कर रहा है। याचिकाकर्ता पाटित कीमतों पर आयात के खिलाफ है।

21. एच ई सी द्वारा की गई आपूर्तियों के बारे में, याचिकाकर्ता को इसके कारणों की जानकारी नहीं है। तथापि, यह कहना पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तु के उत्पादक हैं और उन्होंने सेल को वस्तु की आपूर्ति की है जब सेल विदेशी स्रोतों से अपनी वस्तु को प्राप्त करने में असफल रहा है। अतः याचिकाकर्ता ने आपातकाल में सेल को वस्तु की आपूर्ति की है। निर्दिष्ट प्राधिकारी सेल को इस तथ्य को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का निर्देश दे सकते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु को सेल द्वारा स्वीकार्य पाया गया है।

22. जी पी आई द्वारा आपूर्ति में विलंब के आरोप के बारे में, याचिकाकर्ता ने निवेदन किया कि जी पी आई के कारण आपूर्ति में कोई विलंब नहीं हुआ था। विलंब सेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब के मौखिक अनुरोध के कारण हुआ था चूंकि कंपनी के पास पर्याप्त माल था और उस समय कंपनी के समक्ष कुछ वित्तीय बाधाएं थीं। अतः, जी पी आई द्वारा आपूर्ति में विलंब के आरोप भ्रामक हैं।

ख. सेल द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण:

i) जैसा कि पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, न तो कोई पाटन हुआ है और न ही घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई है। संबद्ध उत्पाद का उत्पादन खुले वैश्विक निविदा आधार पर हो रहा है और भारतीय उद्योगों द्वारा कोट की गई कीमत विदेशी

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कोट की गई कीमत के तुलनात्मक अथवा उससे कम है। पैरा 6,7,8,20, 8.21, 8.23 तथा 8.16 द्वारा पूर्व में किए गए प्रस्तुतीकरणों को दोहराया गया है। न तो कोई क्षति हुई है और न ही इसके लिए कोई कारणात्मक संबंध हैं।

- ii) क्षति का संचयी मूल्यांकन तथा शुल्क का अधिरोपण जैसाकि वर्तमान मामले में अभिकलित किया जा रहा है, पूरी तरह से गलत तथा असमर्थनीय है। याचिकाकर्ता का कीमत ढाँचा घरेलू बाजार में उसके प्रतियोगी अर्थात् एच ई सी की तुलना में अत्यधिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। रिकार्ड में यह भी कहा जा रहा है कि वर्तमान कार्रवाई में एच ई सी द्वारा याचिकाकर्ता को समर्थन दिया जा रहा है। तदनुसार, घरेलू उद्योग की किसी संभावित क्षति पर विचार के लिए एच ई सी की कीमत को संदर्भ कीमत के रूप में लिया जा रहा है।
- iii) निविदा प्रक्रिया द्वारा वस्तु प्राप्ति की सामान्य प्रक्रिया में तकनीक-वाणिज्यिक विनिर्देशनों को पूरा कर सकने की क्षमता रखने वाले निविदाकर्ताओं की एल 1 कीमतों को मानक के रूप में लिया जाता है यदि उनकी कीमतें अनुमानित लागत की स्वीकार्य श्रेणी के भीतर हों। तकनीकी-वाणिज्यिक विनिर्देशनों को पूरा करने वाले अन्य निविदाकर्ताओं को एल 1 कीमतों की समकक्षता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। याचिकाकर्ता जीपीआई को कई बार अन्य घरेलू निविदाकर्ताओं, जैसे वर्तमान मामले में एच ई सी, द्वारा कोट की गई कीमत की समक्षकता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया है। घरेलू उद्योग तथा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के बीच निष्पक्ष प्रतियोगिता पहले से ही विद्यमान है। वर्तमान प्रक्रिया को निष्पक्ष प्रतियोगिता समाप्त करने तथा आपूर्ति का एकमात्र उपलब्ध स्रोत बनने (एकाधिकार संबंधी पहुंच) के एकल लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया है जो पाटनरोधी शुल्क का विषय नहीं हो सकता है।

- iv) अधिसूचिता अधिसूचना में निर्देशित की गई घरेलू उद्योग की क्षमताएँ अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होती हैं चूंकि जीपीआई एवं एचईसी लंबित आदेशों के विरुद्ध समय पर वितरण करने में असमर्थ रहे हैं। तथ्यात्मक रूप में, कई मामलों में सेल को लंबित आदेशों को एच ई सी से परिवर्तित करने पर बाध्य होना पड़ा।
- v) अनुबंध II में उन रोलस को निर्देशित किया गया है जिन्हें एच ई सी तथा जी पी आई द्वारा समय पर वितरण करने में असफल रहे। इनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाकर आयातों को प्रतिबंधित करने की स्थिति में जी पी आई तथा एच ई सी साथ मिल कर भी सेल की सारी आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ होंगे।
- vi) यह सेल का अनुभव है कि एच ई सी तथा जी पी आई द्वारा किए गए वितरणों में अत्यधिक विलंब हुआ है जिसके कारण उत्पादन कार्यक्रम को बनाए रखने में गंभीर समस्याएँ हुई हैं। इसे सेल द्वारा उपलब्ध कराए गए वितरण संबंधी विवरणों से देखा जा सकता है।
- vii) जी पी आई द्वारा कुछ आदेशों को वितरण में किया गया विलंब 0 मास - 1 वर्ष 4 मास की रेंज में है। एच ई सी द्वारा किया गया विलंब 0 मास- 5 वर्ष 6 मास की रेंज में है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में सेल को लंबित आदेशों को अनापूर्ति/विलंब के कारण मै0 एच ई सी से परिवर्तित करने पर बाध्य होना पड़ा।
- viii) जी पीआई संबद्ध वस्तु के कुल उत्पादन के 50% से अधिक का उत्पादन करता है, इसकी पुनः जांच किए जाने की आवश्यकता है चूंकि आई एच एफ रोलस के लिए उनकी प्रोसेसिंग सुविधा सीमित है और उनके पास गढ़ाई तथा रिक्त खाने बनाने की सुविधाएं नहीं है।

- ix) मै0 जीपीआई के पास सिल्ली बनाने तथा रिक्त खानों की गढ़ाई की बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं जो कि आई एच एफ रोल्स के विनिर्माण के लिए एक पूर्वापेक्षा है। यहाँ तक कि उनके पास 600 मि.मी. व्यास से ऊपर के आकारों में रोल्स बनाने की सीमा है।

ग. रूस द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण:

- i) निर्यातकों ने निवेदन किया है कि रूस के लिए 79.91% की दर से निर्धारित किया गया शुल्क एक गलती का परिणाम है। प्राथमिक जाँच परिणामों में दिए गए आंकड़ों से, यूक्रेन के पास उच्चतम पाटन मार्जिन है अतः इस देश के उत्पादों पर उच्चतम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाएगा। नीचे बताई गई संयुक्त पूंजी कंपनी के तर्कों को अस्वीकृत किए जाने के मामले में, रूस के उत्पादों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की राशि यूक्रेन के लिए निर्धारित पाटनरोधी शुल्क से अधिक होगी। टैरिफ (दरों) तथा व्यापार पर सामान्य करार की मद 2 से जारी रखते हुए रूस के लिए पाटनरोधी शुल्क की दर हमारे देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन से अधिक नहीं हो सकता और यह 31.43% बनेगा।
- ii) भविष्यावधि के लिए एक विशेष शुल्क का संग्रहण की योजना बनाई गई है, अतः इस शुल्क पर निर्णय लेने के समय विद्यमान स्थिति पर विचार करना आवश्यक है। विशेष शुल्क का संग्रहण टैरिफ (दरों) एवं व्यापार पर सामान्य करार के खंड 6 की मद 1 का खंडन करता है। खंड 6 की मद 1 के अनुसार पाटन को एक ऐसी स्थिति के रूप में समझा जाता है जब एक देश की वस्तु को दूसरे देश के बाजार में क्रेता देश से उद्गम वाली वस्तु के सामान्य मूल्य से कम कीमत पर आयात किया जाता है।
- iii) रोल्स की कीमत का निर्धारण भारतीय पक्षकार द्वारा किया जाता है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता तथा यह मुक्त

अंतर्राष्ट्रीय निविदा के सभी भागीदारों के लिए समान है। अतः भारत को आपूर्ति किए जाने वाले रोल्स की कीमत एक सामान्य कीमत है। इसके अलावा, जैसाकि भारतीय पक्षकार द्वारा रूस के लिए एक विशेष शुल्क के प्रारंभिक निर्णय में निर्देशित किया गया है, गोंटरमान पाइपर (इंडिया) लि० ने गढ़े हुए रोल्स के मात्र एक पायलट हैच का उत्पादन किया जिसे वह बेच नहीं सका। भारतीय पक्षकार की सूचना से जारी रखते हुए कम्पनी ने मात्र अप्रैल, 2002 में ठंडे गढ़े हुए रोल्स का उत्पादन शुरू किया। अतः, जांच के अंतर्गत आने वाली अवधि में गोंटरमान पाइपर (इंडिया) लि० भारतीय बाजार में उपस्थित नहीं था और रूसी रोल्स के वितरण के कारण उसके अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ था। इस परिस्थिति में, रूसी पक्षकार के कार्यकलापों को कोई पाटन उपलब्ध नहीं है।

- iv) टैरिफ तथा व्यापार पर सामान्य करार दो बार पाटनरोधी शुल्क के संग्रहण की संभावना उपलब्ध नहीं कराता है। रूस के लिए पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण पहले ही 25% की दर से हुआ था।
- v) भारतीय पक्षकार द्वारा एक कंपनी के रूप में उल्लिखित, याचिका का समर्थन कर रहे हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) द्वारा जांच के लिए विषय, रोल्स का उत्पादन नहीं किया जाता है। हम यह सोचते हैं कि गोंटरमान पाइपर इंडिया लिमिटेड की याचिका को इस प्रकार का समर्थन प्रचालित नहीं होता।
- vi) रूसी संघ की ओर से 'यूरलमैश प्लांट' संयुक्त कंपनी के समर्थन के मानक अनुपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त, रूसी संघ में वर्तमान में लागू मुद्रा एवं सीमाशुल्क विधान काफी हद तक निर्यात के विकास में बाधा डालता है और इस प्रकार वस्तु के निर्यात में लगे संगठनों का समर्थन करता है।

घ. भारतीय अलौह धातु विनिर्माता एसोसिएशन तथा मै0 अग्रवाल मेटल वर्क्स प्रा0 लि0 के प्रस्तुतीकरण:

- i) हमने अपनी एसोसिएशन की बैठक में मामले पर विचार-विमर्श किया है। एसोसिएशन की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि रोल्स के आयात पर पाटनरोधी शुल्क वर्तमान में अनुचित है चूंकि भारत में उपलब्ध विनिर्माण क्षमता मात्रा, गुण एवं आकारों में प्रयोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और हम अनुभव करते हैं कि रूस, यूक्रेन तथा कोरिया से गढ़े हुए रोल्स का आयात घरेलू विनिर्माताओं के लिए खतरा नहीं है।
- ii) इसके अतिरिक्त, रोल्स के भारतीय विनिर्माताओं के पास संसेचन, ढलाई, छपाई, गढ़ाई, ऊष्मा शोधन तथा पिसाई से शुरू करके एक समग्र प्लॉट नहीं है। वस्तुतः, भारत में रोल्स विनिर्माताओं के पास मात्र ऊष्मा शोधन प्रक्रिया है जबकि अधिकतर कच्चे माल का आयात होता है। भारत में छोटे व्यास की गढ़ाई का विकास सफलतापूर्वक हो रहा है जिसे रोल्स के भारतीय विनिर्माता रोलिंग मिल अनुप्रयोग के लिए स्टील रोल्स में उनको परिवर्तित करने के लिए प्राप्त कर रहे हैं।
- iii) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार करना बहुत अपरिपक्व होगा और इस पत्र द्वारा हम रोल्स के किसी पाटनरोधी शुल्क के लगाए जाने पर हमारी आपत्ति को पंजीकृत कर रहे हैं।

ड. प्राधिकारी द्वारा जांच

1. क्षति:

नियम 11, अनुबंध-II के तहत जब क्षति के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है तो इस प्रकार के निष्कर्ष में "...पाटित

आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनके प्रभाव तथा इस प्रकार की वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण शामिल होगा। पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि पाटित आयातों के कारण भारत में समान वस्तुओं की कीमत की तुलना में कीमत में कोई उल्लेखनीय गिरावट आई है अथवा नहीं अथवा क्या इस प्रकार के आयातों से कीमतों में अन्य उल्लेखनीय स्तर तक गिरावट आई है, अथवा कीमत वृद्धि में अन्यथा रूकावट आई है जो कि अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ गई होती;

भारत में घरेलू उद्योग पर प्रभाव की जांच के लिए प्राधिकारी ने क्षमता उपयोग उत्पादन, बिक्रियाँ, निवल बिक्री प्राप्ति, लाभप्रदता आदि जैसी उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले अभिसूचकों पर भी विचार किया। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति को सूचित करने वाले विभिन्न मापदंडों पर भी विचार किया गया जो निम्नानुसार हैं:-

प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों पर विचार किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन 01.04.2002 और उसके बाद घोषित किया अतः, क्षति मापदंडों को पृष्ठभूमि में देखा जाना है।

(i) संचयी निर्धारण

भारतीय पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II(iii) में यह व्यवस्था है जिस मामले में किसी उत्पाद का आयात एक से अधिक देशों से हुआ हो ओर उनकी एक साथ पाटनरोधी जांच हो रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का

संचयी रूप से मूल्यांकन करेंगे । प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन नियम सीमाओं से अधिक है । विभिन्न देशों से आयातों की मात्रा निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है । आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उचित है चूंकि संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित वस्तु से भारतीय बाजार में सीधी प्रतियोगिता करते हैं । अतः प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से घरेलू उद्योग को क्षति का संचयी मूल्यांकन किया है ।

(ii) उत्पादन तथा क्षमता उपयोग

कम्पनी ने 01.04.2002 से अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है । महत्वपूर्ण निवेशों तथा पर्याप्त पूर्व परीक्षण के बावजूद, कम्पनी अत्यधिक गैर-लाभकारी कीमतों के कारण इष्टतमरूप से उत्पादन करने में समर्थ नहीं है । यद्यपि उत्पादन तथा क्षमता उपयोग जांच अवधि के दौरान 1999-00 में हुए 318 एम.टी. से बढ़कर 654.25 एमटी तथा 1999.00 में हुए 19.27% से बढ़कर 31.71% हो गया है । परंतु इसे उत्पादन तथा क्षमता उपयोग जो वह प्राप्त कर सकती थी, के संकेतकों के संबंध में देखा जाना है ।

(iii) बिक्रियां

कंपनी की बिक्री मात्रा जो 1999-00 में 189 एम टी थी, जांच अवधि के दौरान बढ़कर 702.86 एम टी हो गई । कम्पनी की जांच 6 उत्पादन को बड़ी मुश्किल से बेचा जा सके, क्योंकि याचिकाकर्ता को प्रस्तावित कीमतें बहुत है गैर-लाभकारी थीं । यह भी नोट करना संगत है कि उत्पाद को सामान्यतौर पर विभिष्ट ग्राहक जरूरतों के लिए तैयार किया जाता है, इस प्रकार, उत्पादन तथा प्राप्त आदेश प्रभावित बिक्रियों से अधिक संगत हैं ।

(iv) उत्पादकता

घरेलू उद्योग की उत्पादकता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। याचिकाकर्ता स्थाई आदेशों की अनुपस्थिति में इष्टतम रूप से उत्पादन करने में समर्थ नहीं रहा है। इसके कारण उत्पादकता कम होती जा रही है।

(v) कीमत कटौती

संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है, परिणामस्वरूप कीमत कटौती करनी पड़ी। रू० . *** /एम.टी की उचित बिक्री कीमत के मुकाबले, रूस के संबंध में आयातों का पहुंच मूल्य रू० *** /एम.टी, यूक्रेन के संबंध में रू० *** /एम.टी तथा कोरिया गणराज्य के संबंध में रू० *** /एम.टी था। इसके अलावा, बहुत से आदेशों में ग्राहकों ने घरेलू उद्योग को आयातित उत्पाद की कीमत के बराबर करने के लिए बाध्य किया है। बहुत ही गैर-लाभकारी कीमतों के बावजूद, घरेलू उद्योग के पास इन आदेशों को, ऐसी कम कीमतों पर जोकि तनिक भी लाभकारी नहीं थीं और जिससे घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत की वसूली भी नहीं हुई, स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

(vi) कम कीमत पर बिक्री

घरेलू उद्योग को आयातित उत्पाद की कम कीमतों को ध्यान में रखते हुए उसके उत्पाद को उत्पादन लागत से काफी कम कीमतों पर बेचने को बाध्य किया गया है। चूंकि, ग्राहकों ने घरेलू उद्योग से सम मूल्य की मांग की है, कम कीमत पर बिक्री, कीमत कटौती की तुलना में घरेलू उद्योग द्वारा आई गई क्षति को भली-भांति प्रतिबिम्बित करता है।

(vii) पाटन मार्जिन

पाटन मार्जिन न सिर्फ निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि बहुत ही अधिक है। अत्यधिक पाटन घरेलू उद्योग को काफी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है।

(viii) नकद प्रवाह

जैसाकि याचिकाकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया, विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत से कम पर बिक्री का कम्पनी के नकद प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अंतर्वाह की तुलना में अत्यधिक नकद बहिर्वाह के कारण नकद प्रवाह ऋणात्मक हो रहा है।

(ix) वस्तु सूचियाँ

चूंकि संबद्ध वस्तुओं को विशिष्ट ग्राहक जरूरतों के अनुसार प्रचुर रूप से बनाया जाता है, घरेलू उद्योग के पास सिर्फ ग्राहकों से संपुष्ट आदेशों पर ही उत्पादन करने का विकल्प था। ऐसी स्थिति होने के कारण, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वस्तु सूचियाँ घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाने के लिए अत्यधिक संगत नहीं होंगी।

(x) विकास

घरेलू उद्योग अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। घरेलू उद्योग से परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट में प्रक्षेपणों के अनुसार समुचित विकास का अनुमान किया गया था, दिया गया कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि में ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। तथापि, अत्यधिक पाटन घरेलू उद्योग के विकास को प्रतिकूल रूप से कम कर रहा है। इसके अलावा, भारी पाटन जिसका याचिकाकर्त्ता बाजार में की गई पेशकश के बावजूद भी अब सामना कर रहा है, को ध्यान में रखते हुए उत्पाद और परियोजनाओं में अपने नियोजित निवेश को पूरा करने में अत्यधिक कठिनाई महसूस कर रहा है।

(xi) नये निवेश बढ़ाने की क्षमता

कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट से देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता सुनियोजित निदेशों को पूर्ण रूप से पूरा करने/उपयोग करने में समर्थ नहीं रहा है। परियोजना के चरण-1 से याचिकाकर्ता को विपणन संबंधी भारी समस्या पैदा हो गई है क्योंकि वह कीमतें जिसे याचिकाकर्ता बाजार में प्राप्त कर रहा है (स्थापित ग्राहकों जैसे सेल से सामग्री की स्वीकृति के बावजूद) इष्टतम से कम है।

(xii) उत्पादन लागत, बिक्री कीमत तथा लाभप्रदता

जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, वह कीमत जिस पर कम्पनी को उत्पाद बेचने के लिए बाध्य किया गया है, से उचित उत्पादन लागत की वसूली नहीं हो सकी। कम्पनी को अत्यधिक वित्तीय घाटे उठाने को बाध्य किया जाता है।

(xiii) घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा

प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने नई उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की है। याचिकाकर्ता ने 01.04.2002 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। जबकि याचिकाकर्ता को इस जांच उत्पादन को बनाने तथा बेचने में वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है, यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता बाजार में उपलब्ध पाटित आयातों के सामने अपने आपको संबद्ध वस्तुओं के नये उत्पादक के रूप में स्थापित करने में समर्थ नहीं है। प्राधिकारी इस संदर्भ में नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का उत्पादन तथा क्षमता उपयोग बहुत ही कम है जितना कि घरेलू उद्योग हासिल कर सकता था। दिया गया है कि शामिल वस्तुओं की प्रकृति जहां उत्पादन सिर्फ स्थाई आदेश के लिए किया जा सकता है, प्राधिकारी का विचार है कि लाभकारी कीमतों पर आदेश की कमी एक उत्पादक को किसी उत्पाद

को तैयार करने तथा बेचने से रोकेगा जिसके लिए उसने नई सुविधाओं की स्थापना की है। ऐसी स्थिति, यदि लम्बे समय तक बनी रहती है तो न सिर्फ घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होगी बल्कि उसके सम्पूर्ण अस्तित्व को भी खतरे में डाल देगा।

2. कारणात्मक संबंध:

यह निर्धारित करने में कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों द्वारा हुई थी, प्राधिकारी ने निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा:-

- (i) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटित कीमतों पर पर्याप्त आयात ने घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमतें गैर-लाभकारी स्तर तक घटाने को बाध्य किया, जिसके कारण भारतीय बाजार में कीमत कटौती की स्थिति उत्पन्न हुई है।
- (ii) संबद्ध देशों से आयातों ने भारतीय बाजार में उत्पाद की कीमतों को उस सीमा तक कम कर दिया कि घरेलू उद्योग अपनी पूरी उत्पादन लागत की वसूली न कर सका तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री से उचित लाभ कमाने से वंचित रह गया।
- (iii) प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध माल का आयात इस देश में हुए कुल आयात का 66.85% रहा। संबद्ध देशों से हुए आयातों का हिस्सा कुल आयातों की तुलना में रूस के मामले में 17.07%, यूक्रेन के मामले में 23.9% और कोरिया जनवादी गणराज्य के मामले में 25.88% रहा है। संबद्ध देशों/क्षेत्रों से हुए आयात जो वर्ष 1999-00 में कुल आयात के 25.5% रहे थे, बढ़कर जांच की अवधि में ये कुल आयात के 66.85% हो गए। इस प्रकार, मात्रा संसंबंधी क्षति स्पष्टरूप से साबित हो गई है। कीमत की दृष्टि से प्रभाव की जांच में प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से किए गए कम कीमत वाले आयातों के कारण याचिकाकर्ता को जांच अवधि के दौरान संबद्ध माल कम कीमत पर बेचने को बाध्य होना पड़ा और इसकी बिक्री में

हानि उठानी पड़ी । संबद्ध माल के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में यथोचित लाभकारी बिक्री कीमत प्राप्त करने में बाधा पहुंची है । घरेलू उद्योग को पाटित आयात कीमतों को बराबर करने के प्रयास में अक्षतिकर कीमत से कम कीमत पर बिक्री करने पर बाध्य होना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग उसे पूरा नहीं कर सका ।

- (iv) जांच-अवधि के दौरान अन्य देशों से किए गए आयात पिछले वर्षों की तुलना में कम रहे हैं और इन देशों की कीमतें अपेक्षतया अधिक रही हैं । प्राधिकारी को मांग में गिरावट, खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां और उनके बीच प्रतिस्पर्धा का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ । यह भी नोट किया जाता है कि प्रौद्योगिकी में विकास होना घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए कोई कारण नहीं रहा है ।
- (v) यह साबित करने में कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों से हुए आयातों के कारण हुई है, प्राधिकारी निर्णय देते हैं कि संबद्ध देशों से किए गए आयातों का बाजार-हिस्सा बढ़ने के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता अर्थात् घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई, यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता ने संबद्ध माल के उत्पादन हेतु नई सुविधाएं स्थापित की हैं । इन आयातों के कारण घरेलू उत्पाद की कीमतों में जबर्दस्त गिरावट आई जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को माल अलाभकारी कीमतों पर बेचने हेतु बाध्य होना पड़ा । इसलिए, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण हुई है ।

3. लैण्डेड मूल्य

संबद्ध माल के लिए लैण्डेड मूल्य का निर्धारण भारित औसत सीआईएफ कीमत में सीमाशुल्क कर की लागू सीमा (धारा 3, 3(क),

8 ख, 9, 9 (क) के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर) और 1% लैंडिंग प्रभार जोड़कर किया जाता है ।

4. गैर-हानिकर कीमत

घरेलू उद्योग के संबंध में समान वस्तुओं के लिए गैर-हानिकर कीमत का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने आदर्श सर्वोत्तम खपत मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग के संबंध में अनुकूलतम उत्पादन लागत निर्धारित करने हेतु संबद्ध माल की वास्तविक उत्पादन-लागत और जांच अवधि के दौरान संबद्ध माल के उत्पादन में खपत किए गए कच्चे माल की वास्तविक कीमत का प्रयोग किया है । क्षति-मार्जिन की गणना के प्रयोजनाथ प्राधिकारी ने जांच-अवधि के लिए निर्धारित एम्स-फैक्ट्री गैर-हानिकर कीमत की तुलना आयातित माल के लैण्डेड मूल्य से की है ।

5. पाटन मार्जिन तक शुल्क:

प्राधिकारी पाटन-मार्जिन के बराबर अथवा कम राशि के पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं जिसे लागू किए जाने से घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त होगी ।

छ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे:

- i) प्राधिकारी निर्णय देते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्यतया पाटन को समाप्त करना, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होती है और भारतीय बाजार में मुक्त एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनर्स्थापित करना है जो देश के सामान्य हित में है ।
- ii) प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध माल प्रयुक्त कर विनिर्मित उत्पादों के कीमत-स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकेगा और इसके फलस्वरूप वह इन उत्पादों की संबंधित प्रतिस्पर्धा पर कुछ प्रभाव डाल सकेगा । किन्तु, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी उपायों द्वारा कमी नहीं आएगी । इसके

विपरीत, पाटनरोधी उपाय लागू करने से पाटन पद्धति द्वारा अनुचित लाभ कमाया जाएगा, घरेलू उद्योग में गिरावट रूकेगी और उपभोक्ताओं को संबद्ध माल के लिए खुला विकल्प मिलने में सहायता होगी ।

- iii) प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लागू करने से रूस, यूक्रेन तथा कोरिया से होने वाले आयातों पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस प्रकार, उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

ज. निष्कर्ष:

उपर्युक्त बातों पर विचार करने के पश्चात् यह देखा जाता है कि-

- (क) संबद्ध देशों के उद्भव अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल का भारत को निर्यात सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया जिससे यहां पाटन हुआ ।
- (ख) भारतीय घरेलू उद्योग को क्षति हुई है । घरेलू उद्योग को उत्पादित संबद्ध माल के संदर्भ में वास्तविक क्षति हुई है । इसके अलावा, घरेलू उद्योग की स्थापना में पाटित आयातों के कारण वास्तविक बाधा आ रही है हालांकि घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में नया संबद्ध उत्पादक लाकर स्वयं को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है ।
- (ग) संबद्ध देशों से संबद्ध माल के आयातों के कारण क्षति हुई है ।
- (घ) यह आवश्यक समझा जाता है कि संबद्ध देशों के उद्भव अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल के आयातों पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगा दिया जाए ।
- (ङ) ऐसा मान लिया जाता है कि पाटन-मार्जिन के बराबर अथवा उससे कम राशि का पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाए जिससे पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति

समाप्त की जा सके । तदनुसार, ऐसा प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय-84.55 के तहत संबद्ध देशों के उद्भव के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल के सभी आयातों पर नीचे दी गई सारण के कालम-9 में उल्लिखित राशि और संबद्ध माल के लैण्डेड मूल्य के अन्तर के बराबर राशि अमरीकी डालर प्रति मी. टन के हिसाब से निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगा दिया जाए ।

क्र. सं.	उपशीर्ष	माल का विवरण	विनिर्देशन	उद्भव का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि (अम. डालर)	यू. मी. टन	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	8455.30	फोर्ड रोल्स	इंडियन हार्डण्ड फोर्ड रोल्स जिसे फोर्ड कोल्ड मिल्स रोल्स के नाम से भी जाना जाता है और जिसमें वर्क रोल्स तथा बैक-प रोल्स शामिल हैं (आकार 300 एम एम ब्यास से अधिक तथा 605 एम एम व्यास तक हो)	कोरिया जनवादी गणराज्य	सभी	कोई भी	कोई भी	2851.91	मी. टन	अम. डालर
2.	8455.30	फोर्ड रोल्स	इंडियन हार्डण्ड फोर्ड रोल्स जिसे फोर्ड कोल्ड मिल्स रोल्स के नाम से भी जाना जाता है और जिसमें वर्क रोल्स तथा बैक-प रोल्स शामिल हैं (आकार 300 एम एम ब्यास से अधिक तथा 605 एम एम व्यास तक हो)	कोई भी देश जिसमें रूस तथा यूक्रेन शामिल नहीं हैं ।	कोरिया गणराज्य	कोई भी	कोई भी	2851.91	मी. टन	3
3.	8455.30	फोर्ड रोल्स	इंडियन हार्डण्ड फोर्ड रोल्स जिसे फोर्ड कोल्ड मिल्स रोल्स के नाम से भी जाना जाता है और जिसमें वर्क रोल्स तथा बैक-प रोल्स शामिल हैं (आकार 300 एम एम ब्यास से अधिक तथा 605 एम एम व्यास तक हो)	यूक्रेन	सभी	कोई भी	कोई भी	2783.05	मी. टन	
4.	8455.30	फोर्ड	इंडियन हार्डण्ड	कोई भी	यूक्रेन	कोई	कोई	2783.05	मी. टन	अम.

		रोल्स	फोर्ज्ड रोल्स जिसे फोर्ज्ड कोल्ड मिल्स रोल्स के नाम से भी जाना जाता है और जिसमें वर्क रोल्स तथा बैक-प रोल्स शामिल हैं (आकार 300 एम एम व्यास से अधिक तथा 605 एम एम व्यास तक हो)	देश जिसमें रूस तथा कोरिया आरपी शामिल नहीं		मी	मी			डालर
5.	8455.30	फोर्ज्ड रोल्स	इंडियन हार्डण्ड फोर्ज्ड रोल्स जिसे फोर्ज्ड कोल्ड मिल्स रोल्स के नाम से भी जाना जाता है और जिसमें वर्क रोल्स तथा बैक-प रोल्स शामिल हैं (आकार 300 एम एम व्यास से अधिक तथा 605 एम एम व्यास तक हो)	रूस	समी	कोई भी	कोई भी	2762.79	मी.टन	अम. डालर
6.	8455.30	फोर्ज्ड रोल्स	इंडियन हार्डण्ड फोर्ज्ड रोल्स जिसे फोर्ज्ड कोल्ड मिल्स रोल्स के नाम से भी जाना जाता है और जिसमें वर्क रोल्स तथा बैक-प रोल्स शामिल हैं (आकार 300 एम एम व्यास से अधिक तथा 605 एम एम व्यास तक हो)	कोई भी देश जिनमें कोरिया आरपी और यूक्रेन शामिल नहीं हैं	रूस	कोई भी	कोई भी	2762.79	मी.टन	अम. डालर

च. उपर्युक्त के अध्यक्षीन प्राधिकारी दिनांक 11 दिसंबर, 2002 के प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं ।

छ. इस आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा स्वर्ण(नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी ।

एल.वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2003

Subject : Anti dumping investigations concerning imports of Induction Hardened Forged Steel Rolls from Russia, Ukraine and Korea RP—Final Findings.

No. 14/3/2002-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof.

A. PROCEDURE:

1. The procedure described below has been followed with regard to the investigations:-

(i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a written application from M/s. Gontermann-Piper (India) Ltd (GPA), West Bengal (hereinafter referred to as Petitioner) on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Induction Hardened Forged Rolls (hereinafter also referred to as subject goods) originating in or exported from Russia, Ukraine and Korea RP (hereinafter referred to as subject country). The petition is also supported by M/s. Heavy Engineering Corporation (HEC) Ranchi.

- (ii) The Authority notified the Embassies of Russia, Ukraine and Korea RP in India about the receipt of petition made by the petitioner before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub rule (5) of Rule 5 supra;
- (iii) The Authority on the basis of information and evidence available before it decided to initiate anti dumping investigations against imports of subject goods from the subject country;
- (iv) The Authority issued a Public Notice dated 27th August, 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping investigations concerning imports of subject goods from subject countries, falling under Chapter Heading 8455 of Schedule I of the Customs Tariff Act.
- (v) The Authority notified preliminary findings vide notification dated 11th December, 2002 on anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from subject countries and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;
- (vi) The Authority forwarded a copy of the preliminary findings to the known exporters, importers and embassies of subject countries in India requesting them to advise the producers and exporters in their countries to respond to the Designated Authority, to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days from the date of its publication;
- (vii) The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the Embassy of Russia, Ukraine and Korea RP in New Delhi with a request that the exporters and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings in the time frame as stipulated in (v) and (vi) above.

(viii) The Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally on 11th February, 2003. All parties presenting views were requested to file written submissions of their views expressed. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any;

(ix) The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request;

(x) Arguments made by the interested parties before announcing the preliminary findings, which have been brought out in the preliminary findings notified have not been repeated herein for sake of brevity. However, the arguments raised by the interested parties subsequently have been appropriately dealt with in these findings;

(xi) In accordance with Rule 16 of the Rules *supra*, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same have also been duly considered in these findings;

(xii) The investigation covered the period from 1st April, 2001 to 30th June, 2002. (fifteen months).

(xiii) **** in this notification represents information furnished by the interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;

B. VIEWS OF PETITIONERS, EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES AND EXAMINATION BY AUTHORITY.

- (i) The product under consideration is Induction Hardened Forged Steel Rolls, also known as Forged CRM (cold rolling mills) Rolls (above 300 mm dia). Forged Rolls are primarily used by steel plants for cold rolling of ferrous and non-ferrous coils obtained from Hot Rolling Mills. These Cold Rolled Coils with fine texture, thin gauge with superior mechanical properties are used for/by:-
- a) Galvanizing Line where cold Roll Coils are coated with zinc and used as roof sheets for Buildings.
 - (b) Equipment manufacturers (OEMs) such as Car Bodies, Scooters, Buses, Auto, Fridges, Washing Machines, Utensils, Cigarette Foils, and Bicycles etc.
- (ii) Forged Rolls are basically made up of vacuum degassed alloy and forged under hydraulic press. The forging is to remove the internal stress and also to refine grains during forging operation. The roll is then spheroidized to the desired microstructure. After machining, the roll is Induction Hardened and also nitrogen quenching is done to achieve maximum hardness. Subsequently the tempered rolls are subjected to final machining. In order to ensure High Quality of Forged Roll, the roll is checked with ultrasonic equipment as also by other quality control equipment at each stage of operations and after final machining before dispatch to customer.

- (iii) Forged Rolls are produced in many sizes. However, the present petition does not include forged rolls below 300 mm size. Forged Roll can be work roll or back up roll. Costs of work rolls and back up rolls vary significantly.
- (iv) Forged Roll is classified under Custom sub-heading No. 8455.30.00 of Chapter 84 of the Customs Tariff Act, 1975.

2. Submissions made by SAIL:

- i) The domestic industry does not produce forged rolls above 600 mm dia.
- ii) The present petition is only against Induction Hardened Forged Rolls. There are several types of rolls, such as work rolls, back up rolls. Petitioner did not want anti dumping duty on these types of rolls, whereas the preliminary findings has recommended anti dumping duty on these types also. These other types of rolls have significantly different cost and price structure.
- iii) The Petitioner has merely given a description of the manufacture of Forged Rolls and its properties and use. Admittedly, the present petition is confined to Induction Hardened Forged Rolls above 300 mm and below 600 mm dia, which are within the production capacity of the petitioner. In view of this admission, the preliminary findings imposing duty on all Rolls above 300 mm dia is incorrect and not sustainable and needs to be dropped/withdrawn. Similarly, there can be no duty proposed or imposed on any other type of Rolls other than Induction Hardened Forged Rolls above 300 mm and below 600 mm which are the only goods under investigation.

- iv) The product under investigation for consideration of anti-dumping duty or otherwise is Induction Hardened Forged Rolls of size above 300 mm and below 600 mm dia. The Chapter Sub-Heading 84.55.30.00 under Custom Tariff Act covers “ROLLS FOR ROLLING MILLS”, thus unless clarified it will cover all rolls even including those which are not the subject goods under investigation.

Submissions made after Disclosure Statement By SAIL

- v) It is appreciated that the authority has agreed to restrict the subject goods to dia (300-600 mm dia). It is again submitted that the products not under investigation be specifically declared as beyond the scope of the present investigations.

3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY:

- (i) The Authority notes that the anti dumping duty in the present case has covered forged rolls (sizes above 300 dia). Further, the petition filed by the petitioner included work rolls and back up rolls. In fact, the export price considered by the petitioner included work rolls and back up rolls. Work rolls and back rolls are also induction hardened forged rolls. The only difference in the two rolls is in specific end application. While one type of roll may be directly employed in rolling the steel, the other type may be indirectly involved in rolling steel. Petitioner had, in fact, specifically stated that forged rolls can be work roll or back up roll. The mere difference in costs and prices does not make them different products.

- (ii) The authority notes that the petitioner can produce Induction Hardened Forge Rolls of size ranging from 300 mm to 605 mm diameter. This position was also found to be correct at the time of visit to the production facilities of the petitioner. The petitioner has produced copies of order placed by Bokaro Steel Plant on the petitioner for supply of subject goods of 605 mm.
- (iii) In view of the above, the Authority restricts the size of the product under consideration up to 605 mm. The Authority confirms the product description as Induction Hardened Forged Rolls (of size ranging from 300 mm – to 605 mm dia) including all types of induction hardened forged rolls, including back rolls and work rolls for the purpose of final findings.

C. Like Article

“Like article means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the article under investigation.

1. Submissions made by the Petitioner:

- (a) There is no viable substitute for forged steel roll. There is no difference in forged steel roll produced by the petitioner and exported from subject countries. Goods produced by the petitioner and imported from subject countries are comparable

in terms of characteristics such as physical characteristics and chemical composition, manufacturing technology, performance, plant & equipment, manufacturing process, functions and uses, marketing & pricing, consumer perception. The two are technically and commercially substitutable. Consumers of Forged Rolls uses the two interchangeably. Therefore, Forged Roll produced by the petitioner and those imported from the subject countries should be treated as like articles in accordance with Anti Dumping Rules.

- (b) There is no known significant difference in the technology adopted by the Indian Industry and the manufacturers in subject countries. The technology adopted by the Indian industry is comparable to the technology adopted by the manufacturers of Forged Steel Rolls in subject countries. However, every manufacturers fine-tunes its production process on the basis of necessities and available facilities.

2. **Submissions made by SAIL:**

- i) The complainant domestic producers M/s. GPI does not have the production facility of the subject merchandise. It has no ingot making and forging facility at its production unit. In absence of the forging facility, GPI cannot be said to be the domestic producer of IHF Rolls, the subject merchandise. Admittedly, it is contended that M/s. GPI buys the blank roll from other sources and then carries process there on like heat treatment and machining so as to supply them under the name and style of Induction Hardened Forged Rolls, the subject

merchandise. Such producer cannot be said to be domestic producer of the subject merchandise and its prices cannot be taken as a normal value of the product. GPI not being the producer and manufacturer of the subject merchandise is not entitled even to file and maintain the present petition for imposition of anti-dumping duty. M/s. GPI has not disclosed the sources wherefrom it is resourcing blanks for processing in its unit. It might be importing them. Such concealment is bad and attracts dismissal of the complaint.

- ii) Important Steps in the Manufacturing Process of Induction Hardened Forged Rolls are –

Steel making and Ingot making, Reheating and Forging, Normalising (Heat Treatment) – Spheroidizing (Annealing), Tempering, Induction Hardening and Tempering. Proof Machining and Final Machining, besides Testing etc.

- iii) Facilities Available In Domestic Industry (to the best of knowledge of SAIL) :

GPI - They have Heat Treatment facilities and Machining Facilities only. They do not have Ingot Making & Forging press to make Blanks required as input material for making finished IH Forged Roll. (as can be concluded from the documents submitted by GPI along with their quotation to SAIL regarding the facilities available with them for manufacturing). It is also known that they buy their blanks from domestic/import source. Hence, their prices ought to be higher than manufacturers who make the Blanks by themselves.

HEC - They have all the required facilities for making Blanks, Heat Treatment facilities and Machining facilities. In case of Backup Rolls, they have facilities for sizes up to 25 T only.

- iv) As per SAIL's knowledge, GPI do not have facilities for making Forged Rolls above 605 mm. HEC have facilities for sizes up to 25 T (1300 dia) only, but they are not able to manufacture & supply due to their internal constraints as evident from their pending supplies delayed even up to 5 yrs. SAIL was constrained to divert pending orders from HEC in many cases.
- v) There is a significant difference between the products manufactured by different parties, not only with regard to manufacturing process, technology and equipment but specifically with regard to the Performance Guaranteed by the manufacturers/producers.

Submissions made after Disclosure Statement

- (vi) SAIL have reiterated its earlier submissions.

3. Submissions made by Exporters:

M/s. NKMZ from Ukraine

- i) Analyzing the submitted description of the product manufactured by the Indian manufacturers of rolls, we notice that the production of our rolls greatly differs both regarding the production methods, applied equipment and regarding the chemical composition of the material.
- ii) Routine procedure for cold rolling mill manufacturing alongwith material/process description have been given.
- iii) High quality of cold rolling mill work rolls of JSC NKMZ production is defined by the following:
 - use of special heat – resistant alloy steel 60 X 2 CM Φ provision of metal high quality by means of efficient ladle refining and vacuum degassing.
 - Use of special modes of rolls forging and induction hardening providing considerable depth of hardened case with high level of physical and mechanical properties and good distribution of residual stresses which assures their durability in the service and also under conditions of high speed rolling.

Cold rolling mill work rolls made of 60 X 2 CM Φ steel differ from rolls of 9 X 2 M Φ steel by the following:

- chemical composition;
- high hardenability and hardness penetration.
- less brittleness;
- increased heat stability.

Metal for rolls is characterized by improved complex of physical and mechanical properties, high isotropy over the whole section. Operating durability of work of 60 x 2 CM Φ steel at different cold rolling mills is 1.3 – 1.7 times higher than that of rolls made of 9 X 2 M Φ steel by Indian makers.

In addition we would like to note that NKZ has the certificate of TUV NORD Co. which certifies that JSC NKMZ has introduced Quality Assurance System in conformity with the international standard ISO 9001 in the field of development, designing, manufacture and erection of metallurgical facilities.

Submissions made after Disclosure Statement

- iv) No submissions have been made by the exporters.

4. Examination by the Authority

- i) The Authority notes that one of the exporters from Russia have indicated that the domestic industry do not produce the goods of the quality as desired by the Indian user industry. M/s. NKMZ from Ukraine have asserted that their rolls differs both regarding the production method and regarding the chemical

composition of the material. However, there are no claims to this effect by the user industry and that even such claims have not been substantiated. Though it has been claimed that technology has been different, impact of this aspect on normal value could not be worked out as exporters have not fully cooperated.

- ii) With regard to the argument that the petitioner does not hold facility for production of forged blanks, the Authority notes that the product under consideration in the present petition is induction hardened forged rolls. Forged blanks are raw material to production of forged rolls. Even though it is possible that some of the producers are backward integrated in as much as they produce forged blanks and forged rolls, the two constitute two different and distinct products. It can be said that a producer must possess facilities for production of forged blanks also before it can be described a producer of forged rolls.
- iii) The Authority also notes that the petitioner has supplied these goods to M/s. Rourkela Steel Plant, Katni, M/s. Agarwal Metals, Jaipur, M/s. Bhusan Steel, M/s. Hero Cycles, M/s. Ispat Industries Ltd., M/s. ITW Signotec India Ltd., M/s. Jindal Industries Ltd., M/s. JISCO (Tarapur), M/s. JISCO (Vasind), M/s. Lloyds Steel, M/s. Lyka Engg., M/s. National Steels, M/s. Nezone Strips, M/s. Ruchi Strips and Alloys Ltd., M/s. Shree Precoates, M/s. Stelco Gujarat, M/s. Surya Rosini, Indian Melting and Refining CO., Ltd., M/s. Tinplate Co., M/s. Uttam Steel, M/s. Vallabh Steel and M/s. Walzen Strips.

- iv) In view of the foregoing, the Authority holds that the goods exported from the subject countries and those produced by the Domestic Industry, as like article as per Rule 2 (d) for the purpose of final findings.

D. Initiation, Standing and Domestic Industry

The petition has been filed by M/s. Gontermann-Peipers (India) Limited, West Bengal on behalf of the domestic industry. The petitioners have claimed that they account for 54.46% of the total Indian production of the subject goods. M/s. Heavy Engineering Corporation (HEC) with a standing of 45.55% has supported the petition filed by the petitioner. As per 5(3) of the anti dumping rules, Designated Authority shall not initiate any investigations pursuant to the application made under sub rule (a) unless it determines on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to the application expressed by domestic producers of the like product that the application has been made by or on behalf of the domestic industry provided that no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than 25% of the total production of the like article by the domestic industry. It has also been explained in the sub rules that the application is deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry if it is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than 50% of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition as the case may be to the application.

1. **Submissions made by SAIL:**

- i) SAIL's annual requirement of Forged Rolls are around 4000 T as indicated at Annexure. The IHF Rolls constitute only around 25% of the total requirement of Forged Rolls of SAIL. The Forged Rolls required by SAIL are even up to 45 T in weight & upto 1610 mm dia each. M/s. GPI does not have facility to produce and meet the total requirement of SAIL
- ii) It was conceded by the Petitioners during the Public Hearing, that they are the only private company having Induction Hardening and Machining facilities for Induction Hardened Rolls of sizes 300-605 mm diameter and they do not have the Steel Making & Blank making facilities. Regarding M/s. TAYO, Jamshedpur, the petitioner has stated that mere final machining or finishing of the product does not constitute "production" nor does the company have facilities required for producing IHF Rolls. It can be concluded from the view of the petitioner that on the same lines, since GPI also has only Induction Hardening and Machining facilities and they do not have steel making & forging facilities, they also cannot be considered as a "producer" of I H Forged Rolls. On this basis, GPA could only be considered as a trader as they do not have the required steel making facility, technology and expertise essential for producing Induction Hardened Forged Rolls.

- iii) GPI does not have production facilities to produce the goods. It does not have ingot making and forging facilities. Important steps in production of rolls are steel making, ingot making, reheating, forging, normalising, spheroidizing (annealing), tempering, induction hardening tempering, proof machining and final machining. GPI does not have all these facilities. While HEC has all these facilities, it is not able to supply due to their internal problems.
- iv) Capacities claimed by the petitioner appear exaggerated, since these companies have not been able to supply.
- v) Even HEC and GPI would not be able to cater to the full requirement of SAIL.
- vi) Since the company has commenced commercial production only from last 2-3 years, it can not claim injury, as it does not have full manufacturing facilities and created only final processing facilities only in the last two years.
- vii) In view of the above, the petitioner are not the producer of the subject product and are not entitled to file and maintain this petition for imposition of anti dumping duty. The petitioners are trying to gain advantage by unfair trade practices whereby they are trying to unfairly eliminate the roll producers giving very little choice to the Indian customer not only on the quality but also on the products/prices.

2. **Submissions made by Ukraine:**

- (i) It is submitted that the price for cold rolling mill work rolls supplied to the Indian market is at the level of prices for the similar rolls supplied by NKMZ to the home market and countries of CIS. To our mind, the petitioner, namely : private company Gonterman – Peipers Ltd does not come out on behalf of industrial majority and they do not represent more than 50% of the total production of similar goods and given in the document importer's point of view is unconvincing, because it is presented by one company only "Tinplate Co. of India Ltd." but opinion of such large importers of JSC NKMZ products as SAIL Rourkela, Bokaro Steel Plant Rourkela Steel Plant is not presented in the document.

3. **Examination by the Authority:**

- (i) The Authority notes that it is not necessary that the petitioner should undertake production from basic stage. No cogent reasoning has been adduced to establish why production from the stage of forged blank does not constitute production within the meaning of the Anti Dumping Rules. Moreover, it seems to have been assumed that production of forged blanks would not involve efforts. It has not been established that the company has been forced to pay significantly higher prices for forged blanks.

- (ii) The Authority notes that Rule 2 (b) lays down definition of domestic industry, inter-alia, “ means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of like article and any activity connected therewith.....”. In view of this rule position, the petitioners are to be treated as part of the domestic industry.
- (iii) In view of the above, the Authority holds that petitioners satisfy the criteria of standing to file the petition on behalf of the Domestic Industry in terms of rules 5 (3) (a) of the Rules supra. The Authority also considers these petitioner companies as ‘domestic industry ‘within the meaning of Rules 2(b) supra.

E. De-Minimus Limit

The imports of the subject countries are reported in terms of “nos”. However the information collected from secondary sources by the petitioner suggested that the import are being reported in number of different units like numbers, weight PCs and meters. Further in case of nos. one large size Forged CRM Rolls and one small size Forged CRM Rolls would become two whereas, value of these two would be significantly different. As regard ascertaining that the imports from the subject countries during the period of investigation are above de-minimus levels, authority has referred to the Secondary sources submitted by petitioners (viz.: Infodrive India and tender information) published data for the POI. The Authority has assessed import volumes in terms of weight of forged blanks to assess whether imports from a particular country were beyond de-minimus. Share of imports from the three Countries are given below.

Country name	Quantity MT	% Share
--------------	-------------	---------

Russia	*****	17.07
Ukraine	*****	23.9
Korea	*****	25.88

Thus the Authority finds that the imports from the subject countries during the POI are above de-minimus level.

1. **Normal Value & Export Price :**

Normal value in relation to an article implies

- (a) Comparable price, in ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory.
- (b) When there are no sale of the like articles in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market, of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either
 - (a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriated third country, or
 - (b) The cost of production of the subject goods in the country of origin along with reasonable addition for the administrative, selling and general costs and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6).

Provided that in the case of imports of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely trans-

shipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with section with 9A(1)(c) of the Custom Tariff Act.

a) **Submissions made by Ukraine:**

- i) The exporter has submitted that one cannot agree with the statement that Ukraine is a country with the non-market economy. As is generally known the market economy is based on the development of the social division of labour, commodity production and exchange. In the market in the course of competition prices formation and movement and shaping of demand and offer proceed. Every private commodity producer in the process of exchange of his goods for money gets to know how much his labour is necessary for the society, involved in the system of social division of labour and how much it has acquired social nature.
- ii) The efficient functioning of the market economy suggests a diversity of forms of property and economic management and a well-developed infrastructure. The market economy has a complicated structure and includes the following kinds of markets:
 - A. Commodity and services market.
 - B. Production factors market

C. Financial or monetary market.

- iii) The economic situation established in Ukraine meets all these requirements. This fact is verified by the current legislation of Ukraine. The above-mentioned relations are governed by the Civil Code, Code of labour legislation, Ukrainian Laws “On prices and price formation”, “ On property”, “On protection against unfair competition”, “On entrepreneurship”, “On enterprises in Ukraine” and a number of the other regulatory and legal acts of Ukrainian and international nature.
- iv) As we have already noted above, JSC NKMZ produces forged rolling mill rolls for more than 60 years and has vast experience in this area. Naturally, we have the adjusted technology for rolls manufacture and low cost for their making. “Gontermann-Peipers Ltd” produces forged rolling mill rolls since recent time and, to our opinion, they would like to enter the Indian market not by means by expenditures reducing for rolls making and, as a consequence, price reduction for rolls, but by exerting pressure on enterprises of Russia, Ukraine and Korea with the aid of anti-dumping investigation.

b) Submissions made by Russia

- (i) The Russian Party in the person of “Uralmash Plant” JSC, has submitted all possible data, requested by the Indian Party, including the data on the roll manufacturing price. The Joint

Stock company has not submitted the information on Form 7 of the questionnaire for the exporters as the contents of this document were not clear. This fact does not mean that the Joint stock company did not submit completely the data on the manufacturing price of the products, as such information was submitted in the other forms of the questionnaire.

- (ii) Besides in the information attached to the questionnaire “Uralmash Plant” JSC told about the necessity to explain how to fill in Form No. 7 in order to submit the required data and about its readiness to submit any requested information, including the information on the manufacturing cost.
 - (iii) The Indian Party has determined Russian as a country of non-market economy in comparison with such countries as USA and countries of the European Union. At the end of 2002 Russia was recognized by the said countries as a country of market economy and the solution is prepared for its affiliation in the World Trade Organization (Russia fully agreed the conditions of enlistment to this Organization with nine countries – members of WTO and the talks with fifteen countries shall be finished to the spring of 2003)
- c) **Submissions made by SAIL:**
- i) The petitioners have made no attempt to establish the alleged dumping, but have taken resort to the contention that the alleged exporting countries are non-market economies. The exporting countries are not non-market economies for the

subject merchandise. Russia is already been recognized as a country of market economy. It would be incorrect to assume Russia or Ukraine as non-market economy, and to impose dumping duty. The assumptions which the petitioners are trying to draw are wholly untenable and no finding can be concluded on the basis on such untenable findings.

- ii) It is further submitted that the Induction Hardened Forged Rolls are not standard products. These Rolls do not have a standard price mechanism, they are supplied and purchased on the basis of weight and specification, which will vary from roll to roll, depending upon the requirement and end-use. Accordingly, the question of non-market economy has no bearing in relation to the subject product.

d) **Submissions made by the Petitioner:**

- i) The Designated Authority sent questionnaires to know exporters/producers in Russia, Ukraine and Korea RP and Embassies of the subject countries in India. However, none of the exporters from Korea and Ukraine responded to the Designated Authority. Therefore, the petitioner requests the Designated Authority to confirm the preliminary findings with regard to these countries.
- ii) With regard to Russia, it is submitted that the exporters have not rebutted the claim of the petitioner that Russia is a non-market economy. Petitioner claimed that Russia is a non-market economy on the basis of Rules, which states as under:-

There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as a non-market economy country for the purpose of an anti-dumping investigation by the Designated Authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a non-market economy country.

Clearly, in case a country has been treated as non-market economy country by any other WTO member country, the country can be considered as non-market economy. Russia has been treated as non-market economy by US and European Union in a number of investigations in general and Structural bars (by US) in particular in the preceding three years period. Petitioner, therefore, submit that normal value has to be determined in accordance with the provisions contained in Rule 7 & 8 of the Annexure – 1.

- iii) Such being the situation, petitioner submits that the issue of providing cost of production or details of sales made in the domestic market has no relevance so far as determination of normal value for Russia is concerned. Such being the situation, the petitioner requests the Designated Authority to confirm the preliminary finding with regard to Russia also.

2. Examination by the Authority:**i) South Korea and Ukraine****(a) Normal Value**

The authority notes that none of the exporters from South Korea or Ukraine have responded by way of questionnaire response. The Authority, in view of non-submission of data and non-cooperation by these countries; has constructed the normal value for all producers and exporters of South Korea & Ukraine on the basis of the best available information as made available by the petitioner in accordance with Rule 6(8) supra. The cost of production as provided by the petitioner with due adjustments has therefore been referenced for the purpose of determination of normal value of the subject goods in South Korea and Ukraine. The normal value so determined for South Korea and Ukraine is US \$ *****per/MT.

(b) Export Price

As regard the export price of the subject goods in the period of investigations the authority notes that in view of no cooperation from any of the exporters/importer, the information on export price is made available from the secondary sources by the petitioner. The authority in view of this confirms the methodology as indicated in preliminary findings dated 11th December, 2001. The authority has considered the adjustments on account of inland freight, port expenses, ocean freight and marine expenses as provided by the petitioner. In respect of South Korea, after allowing these adjustments, the export price comes to \$ *****per/MT. In respect of Ukraine, the adjustments have been considered on the same level as allowed to

Russia. After allowing these adjustments the export price comes to US\$*****per/MT.

ii) **Russia**

(a) **Normal value**

- (i) The authority notes that only one of the exporters/ producers from Russia M/s Uralmashplant has provided domestic price and export price of subject goods to India. The response to the exporters' questionnaire is incomplete. The information required under Appendix-1 has been provided for the year 2000 and not for the period of investigation of April, 2001 to June, 2002. The company has not provided Appendix 7 to the Authority to ascertain the capacity, production as also to enable reconciliation of the Appendixes submitted. The information submitted in respect of factory cost and profit is also incomplete as no information under various cost headings have been provided. The exporter has not submitted its financial statement or other statements.
- (ii) The authority, therefore, in view of the fact that the cost of production of the subject goods has not been adequately made available by the exporter thus not permitting the Authority to apply the ordinary course of trade test, has referenced the normal value claimed by the petitioner on the basis of the constructed cost of production with appropriate adjustment as per Rule 6(8) supra. The Authority has determined the Normal Value as US \$ ***** per/MT in case of all exporters from Russia.

(b) **Export price**

The Authority has referenced the CIF export price on the basis of adjustments on packaging, inland, freight, storage, ocean freight, ocean insurance and documentation cost as provided by the exporter for the subject goods during the period of investigation. The authority in view of this confirms the methodology as indicated in preliminary findings dated 11, December 2001. After allowing these adjustments, the export price is determined as US\$ ***** per/MT.

3. **Dumping Margin:**

Vide Section 9 A (a) of the Customs Tariff Act, 1975 "Margin of Dumping", in relation to an article, means the difference between its export price and its normal value. The dumping margin is as follows:

Country	Russia (all exporters/producers)	Ukraine (all exporters/producers)	Korea (all exporters/producers)
Normal Value	****	****	****
Export Price	****	****	****
Dumping Margin%	79.65	67.51	11.06

F. INJURY AND CAUSAL LINK**a. Views of petitioner:**

1. Petitioners have stated that various parameters collectively and cumulatively establish that the domestic industry is suffering injury.
2. Petitioners provided detailed information to the Designated Authority clearly establishing that the domestic industry has suffered severe injury. Further, dumping is resulting in severe threat of material injury. Petitioners submit that the following parameters summarize injury to the domestic industry.
3. Import of subject goods from the subject countries have increased significantly in absolute terms.
4. Market share of import from the subject countries to total imports of subject in India increased significantly.
5. The share of imports from the subject countries in relation to demand/consumption of subject in India increased significantly.
6. Economic Parameters affecting domestic industry.

Though Production, capacity utilization and hence sales

of the domestic industry increased. However the domestic industry could not achieve the production targeted. The capacity utilization of the domestic industry is quite low, as industry is not able to sell the subject goods due to dumped imports.

The imports forced the domestic industry to sell the product below its fair value, since the domestic industry was forced to match the prices. Thus, the imports forced the domestic industry to sell the product at loss.

7. The landed value of imported material was significantly below the selling price of the domestic industry causing price undercutting in the Indian market.
8. The landed value of imported material is significantly below the cost of production and fair selling price of the domestic industry causing severe price suppression in the Indian market.
9. The domestic industry continues to incur significant financial losses as a result of continued dumping in the Indian Market.

10. Though the selling price of the domestic industry has increased however the industry is still facing losses.
11. The financial losses suffered by the domestic industry adversely affected the cash flow.
12. The domestic industry is not able to raise fresh capital or plan new investments. In fact, petitioner had to stagger implementation of the project.
13. The dumping margin are not only more than de-minimus, but also very significant. Significant dumping margins have very adversely affected the performance of the domestic industry.
14. DUTY IN US \$:

Though the Designated Authority has already recommended anti-dumping duty in terms of US \$, it is submitted that the final duties may also be recommended in terms of US \$ only, so that erosion in the quantum of protection does not take place on account of changes in the exchange rate. However, the duties may please be recommended in terms of reference price as done in preliminary finding.

15. Cumulative assessment of injury:

The parameters laid down under the Rules for cumulative assessment of injury are well met in this case, as (a) quantum of imports from each of the subject countries is more than the de-minimus; (b) dumping margin from each of the subject countries is more than de-minus; and (c) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

Petitioner has already provided detailed information to the Designated Authority clearly establishing that the domestic industry has suffered material injury. Further, dumping is resulting in severe threat of material injury. Petitioners submit that the following parameters summarize injury to the domestic industry.

- i) Imports of subject goods from the subject countries have increased significantly in absolute terms.
- ii) Market share of imports from the subject countries to total imports of subject goods in India increased significantly.

- iii) The share of imports from the subject countries in relation to demand/consumption of subject goods in India increased significantly.

16. Meeting of Demand:

The domestic industry is seeking relief on Induction Hardened Forged Rolls of size 300-605 mm dia. The domestic industry is producing and selling Forged Rolls of these sizes. The domestic industry is able to fulfill the demand of the subject goods of specified sizes. It is further submitted that meeting demand is not a precondition to imposition of anti-dumping duty. In any event, in case there would be a situation of short supply and high prices in future, the Designated Authority has recommended a reference price in this case. Imports at fair prices can always be made by these parties.

17. Criticality of rolls for SAIL

The argument of SAIL more than reinforces the need for anti-dumping duty on the product so that SAIL is assured of the product all the times. In fact, whenever SAIL has not received supplies from foreign producers in time, GPI has come to their rescue and supplied them the critical raw material required by them.

18. Supply of Forged Rolls to SAIL:

The Statement of SAIL regarding GPI not supplying the material in time is not correct. In fact, GPI has come to

rescue of SAIL when SAIL has not received delivery of imported material.

19. Lower prices quoted by HEC in tender:

It needs to be appreciated by SAIL that prices quoted in tender by various tenderer are in consideration of the various parties who are going to participate in the tender. Presence of other suppliers per se affect the prices which other producers would quote. Thus, lower prices quoted by HEC are to be seen in the context of other suppliers present in the market.

20. Production by HEC:

HEC is manufacturing the subject goods. The allegation of the SAIL that HEC is not able to manufacture the subject goods is factually incorrect. It is irrelevant that the company is a BIFR Company. A BIFR Company does not mean that the company is out of production. So long as the company is producing the subject goods, it can seek protection from the dumped imports. In the matter of PIB, though the petitioner was a BIFR company, the anti-dumping duty has been recommended on the dumped imports. Further, petitioner is not opposing any imports at fair prices. Petitioner is against imports at dumped prices.

21. With regard to supplies by HEC, petitioner is not aware of the reasons for the same. However, suffice it to say that petitioner is a producer of the subject goods and has supplied goods to SAIL when SAIL failed to procure its goods from foreign sources. Thus, petitioner has supplied goods to SAIL at the time of emergencies. Designated Authority may kindly direct SAIL to confirm or deny this fact that the goods supplied by petitioner have been found acceptable by SAIL.
22. With regard to allegation of delay in supply by GPI, petitioner submitted that there was no delay in supply on account of GPI. The delay was due to verbal request by SAIL to delay supply of material as the company had sufficient stocks and has some financial constraints at that point of time. Therefore, the allegation of delay in supply by GPI is misleading

b. Submission made by SAIL:

- i) As already submitted, there is neither any dumping nor any injury to the domestic industry. The subject product is being procured by the Open Global tender basis and the price quoted by the Indian industries is comparable or even lower than the price quoted by the foreign suppliers. The submissions made earlier vide Paras 6,7, 8.20, 8.21, 8.23 and 8.16 are reiterated. There is neither any injury nor any causal link to it.
- ii) Cumulative Assessment of the injury and imposition of duty as being computed in the present case is wholly incorrect and untenable. The price structure of the petitioner is itself excessive and exaggerated even in

comparison to its competitor in the domestic market i.e. HEC. It is also being said on record that HEC is supporting the petitioner in the present proceedings. Accordingly, the price of HEC has to be taken as the reference price for the consideration of any probable injury to the Domestic Industry.

- iii) As a normal procedure of procuring goods through the tendering process, the L1 prices of the tenderer who is able to meet the techno-commercial specification are taken as the standard, if the same are within the acceptable range of estimated cost. The other tenderers who qualify the techno-commercial specifications are given chance to match the L1 prices. Several times the petitioner, GPI has been given chance to match the price quoted by the other domestic tenderers, like HEC in the present case. Fair competition between the domestic industry and foreign suppliers already exists. The present proceedings have been initiated with the sole motive of removing the fair competition and to be the single available source for supply (monopolistic approach) which cannot be the object of the Anti-Dumping Duty.
- iv) The capacities of the domestic industry indicated in the notification appears exaggerated, since GPI & HEC have not been able to deliver against the pending orders in time. As a matter of fact, SAIL was forced to divert pending orders from HEC in many cases.
- v) Annexure II indicates the Rolls which HEC and GPI have failed to deliver on time. From this it can be inferred that even GPI and HEC together will not be able

to cater to the full requirement of SAIL, in the event of restricting imports by imposing anti dumping duty.

- vi) It has been SAIL's experience that there are significant delays in the deliveries made by HEC & GPI causing serious problems in maintaining the production schedules. This can be seen from the delivery details provided by SAIL.
- vii) Delays in deliveries in some orders by GPI is ranging between 0 months – 1 yr. 4 months. The delays by HEC are ranging between 0 months – 5 yrs. 6 months. Even in some cases, SAIL was forced to divert pending orders from M/s HEC due to non-supplies / delays.
- viii) GPI accounts for more than 50% of the total production of the subject goods need to be reexamined since their processing facilities for IHF Rolls is limited & they do not have Forging & Blank Making facilities.
- ix) M/s GPI do not have basic facilities of ingot making & Forging of blanks which are a pre-requisite for IHF Rolls manufacturing. Even, they have the limitation of making rolls in sizes above 600 mm. Dia.

c. **Submissions made by Russia:**

- i) The exporters have submitted that the duty determined for Russia @ 79.91% is a consequence of an error. From the data given in the preliminary findings, Ukraine has the maximum dumping margin, hence the maximum

anti-dumping duty shall be imposed on the products of this country. In case of rejection of the arguments of the Joint-stock company stated below, the size of the anti-dumping duty, imposed on the products from Russia shall not exceed the anti-dumping duty determined for Ukraine. Proceeding from item 2 of the General Agreement on Tariff (rates) and Trade, the rate of the anti-dumping duty for Russia cannot exceed the dumping margin, determined for our country, and will make up 31.43%.

- ii) Collection of a special duty is planned for the future period, therefore, it is necessary to consider the situation, existing at the moment of taking the decision on this duty. Collection of the specified duty contradicts item 1 of Clause 6 of the General Agreement on Tariff (rates) and Trade. According to item 1 of Clause 6 dumping is understood as a situation when the goods of one country are imported to the market of the other country by the price lower than normal value of the goods, originating from the country-Buyer.
- iii) The price for the rolls is determined by the Indian Party, it is not subject to alteration and is equal for all participants of the open international tender. So the price of the rolls, supplied to India, is a normal price. Besides, as the Indian Party indicated in the preliminary decision of a special duty for Russia. Gontermann Piper (India) Limited produced only a pilot hatch of forged rolls which it could not realize. Proceeding from the Indian Party's information the company began production of the cold forged rolls only

in April, 2002. So in the period being under investigation, Gontermann Piper (India) Limited was not present at the Indian market and its rights were not infringed by the deliveries of the Russian rolls. In this situation no dumping is available in the actions of the Russian Party.

- iv) The General agreement on tariff and trade does not provide the possibility of collection of anti-dumping duty twice. The anti-dumping duty was already determined for Russia at the rate of 25%.
 - v) The Heavy Engineering Corporation (HEC), mentioned by Indian Party as a company, supporting the petition, does not produce the rolls, being the subject of investigation. We think that such support of the petition of Gontermann Piper India Limited cannot operate.
 - vi) The measures of supporting "Uralmash Plant" Joint Company from the side of the Russian Federation are absent. Moreover, the currency and customs legislation, being in force at present in the Russian federation, hinders, to a great extent, development of export and thus supports the organizations engaged in export of goods.
- d. Submissions by Indian Non-Ferrous Metal Manufacturers Association and M/s Agrawal Metal Works Pvt. Ltd. :
- i) We have deliberated the matter in the meeting of our Association. It was resolved in the meeting of the Association that Anti-dumping duty on import of rolls is

unwarranted at present, since manufacturing capacity available in India is not sufficient to cater the requirement of the users in quantity, quality as well as sizes and we feel that import of forged rolls from Russia, Ukraine & Korea is no threat to the domestic manufacturers.

- ii) Moreover, Indian manufacturers of rolls are not having an integrated plant starting from milting, casting, machining, forging, heat treatment and grinding. Basically, in India the roll manufacturers are having heat treatment process only whereas most of the raw stock is being imported. Small diameter forgings are being developed successfully in India as well which Indian manufacturers of the rolls are procuring for converting them into Steel Rolls for rolling mill application.
- iii) In view of the above, it will be too pre-matured to consider any proposal for imposing Anti-Dumping Duty and through this letter we are registering our objection to imposition of any Anti-Dumping Duty of the rolls.

e. **Examination by the Authority**

1. **INJURY:**

Under Rule 11 supra, Annexure –II, when a finding of injury is arrived at such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, “..... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such

imports on domestic producers of such articles” In considering the effect the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

For the examination of the impact on the domestic industry in India, the Authority also considered such further indices having a bearing on the State of Industry as capacity utilisation production, sales, net sales realization, profitability, etc. . The Authority took into account various parameters indicating injury to the domestic industry, which are as follows:

The Authority has considered arguments of various interested parties for examination of injury to the domestic industry. The Authority notes that the petitioner declared its commercial production from 01.04.2002 onwards, thus, the injury parameters have to be seen in this backdrop.

(i) **Cumulative assessment**

Annexure II (iii) to the Indian Anti Dumping Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti dumping investigations, the designated authority will cumulatively assess the effect of such imports. The margins of dumping from each of the subject country are more than the limits prescribed. Quantum of imports from various countries is more than de-minimus. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the goods offered by the domestic

industry in the Indian market. The Authority therefore has assessed injury to the domestic industry cumulatively from all the subject countries.

(ii) **Production and Utilization of Capacity**

The company has started its commercial production from 01.04.2002. In spite of significant investments and considerable trial runs, the company is not able to produce optimally due to very un-remunerative prices. Though the production and capacity utilisation have improved during the POI to 654.25 mt from 318 mt in 1999-00 and to 31.71% from 19.27% in 1999-00 but the same has to be seen in relation to the indices of production and capacity utilisation it could have achieved.

(iii) **Sales**

Sales volume of the company increased during the POI to 702.86 mt from 189 mt in 1999-00. The trial production of the company could be sold with lot of difficulty, as the prices offered to the petitioner were very un-remunerative. It is also relevant to note that the product is normally made against specific customer requirements, thus, production and orders received are more relevant than the sales effected.

(iv) **Productivity**

Productivity of the domestic industry is getting adversely affected. The petitioner has not been able to produce optimally in the absence of firm orders. This is resulting in lower productivity.

(v) **Price undercutting**

The landed price of imports from the subject countries is considerably lower than the selling price of the domestic industry, resulting in price undercutting. As against the fair selling price of Rs. ****/Mt the landed price of imports in respect of Russia was Rs ****/Mt, in respect of Ukraine was Rs ****/Mt and in respect of Korea RP was Rs.****/mt Further, in number of orders, the customers have forced the domestic industry to match the price of the imported product. In spite of very un-remunerative prices, the domestic industry had no option but to accept these orders at such low prices which were not at all remunerative and did not permit recovery of even cash cost of production to the domestic industry.

(vi) **Price underselling**

The domestic industry has been forced to sell the product at prices much below the cost of production in view of lower prices of the imported product. Since the customers have demanded matching prices from the domestic industry, price underselling better reflects the injury being faced by the domestic industry as compared to price undercutting.

(vii) **Margin of dumping**

The dumping margins are not only more than de-minimus but also very significant. Significant dumping is very adversely affecting the domestic industry.

(viii) **Cash flow**

As submitted by the petitioners, sales of the product under consideration, below cost of production is having adverse impact on the cash flow of the company. Cash flow is remaining negative due to higher cash outflow as compared to inflow.

(ix) **Inventories**

Since the subject goods are largely made as per specific customer requirements, the domestic industry has no option but to produce only against confirmed orders from the customers. Such being the situation, the authority notes that inventories would not be very relevant to reflect the injury to the domestic industry.

(x) **Growth**

The domestic industry is at its nascent stage. The domestic industry was expected to show decent growth as per the projections in the Project Feasibility Report, given that the domestic industry has commenced commercial production in the investigation period itself. Significant dumping is, however, very adversely retarding the growth of the domestic industry. Further, the petitioner is finding it extremely difficult to complete its planned investments on the product and the project in view of severe dumping which the petitioner is now facing even for whatever is offered in the market.

(xi) **Ability to raise fresh investment**

It can be seen from the project feasibility report provided by the company that the petitioner has not been able to fully make/utilize the planned investment. Phase-I of the project itself has met with

serious marketing problems to the petitioner, as the prices the petitioner is getting in the market (in spite of acceptance of the material from established customers such as SAIL) is less than optimum.

(xii) **Cost of production, selling price and profitability**

As mentioned earlier, the price at which the company has been forced to sell the product did not permit recovery of reasonable cost of production. The company is forced to face severe financial losses.

(xiii) **Material retardation to establishment of the domestic industry**

The Authority notes that the petitioner has set up new production facilities. The petitioner commenced commercial production w.e.f 01.04.2002. While the petitioner has suffered material injury in producing and selling this trial production, it is found that the petitioner is not able to establish itself as a new producer of the subject goods in the face of dumped imports being available in the market. The Authority in this regard notes that the production and capacity utilization of the domestic industry is significantly lower than what the domestic industry could have achieved. Given the nature of the goods involved where production can be undertaken only against firm order, the Authority holds that lack of orders at remunerative prices would prevent a producer from producing and selling a product for which it has set up new facilities. Such a situation, if continued for longer, would not only cause material injury to the domestic industry but also jeopardize its entire existence.

2. **Causal Link :**

In determining whether injury to the domestic industry was caused by the dumped imports, the Authority took into account the following facts:-

- (i) Substantial imports of subject goods from subject countries/ at dumped prices forced the domestic industry to reduce its selling prices to unremunerative level, which has resulted in a situation of price undercutting in the Indian market.
- (ii) The imports from subject countries suppressed the prices of the product in the Indian market to such an extent that the domestic industry was prevented from recovering its full cost of production and earn a reasonable profit from the sale of subject goods in India.
- (iii) The Authority notes that imports of subject goods from the subject countries during the POI accounted for 66.85 % of the total imports into this country. The share of imports from subject countries with total imports was 17.07% in case of Russia, 23.9% in case of Ukraine and 25.88% in case of Korea RP. Imports from subject countries/territories have increased from 25.25% in 1999-00 of the total imports to 66.85% of the total imports in the POI. Thus, volume injury is clearly established. In examining the price effect, the Authority notes that the low priced imports from the subject countries has forced the petitioner to sell at suppressed prices and incur losses on the sale of the subject goods during the period of investigation. Dumped imports of subject goods have prevented the domestic industry from realizing a reasonable remunerative selling price in the domestic market. The domestic industry in its attempt to match the dumped import prices was forced to sell below its non-injurious price, which resultantly, the domestic industry was unable to recover.

- (iv) Imports from other countries have been much less during the POI as against previous years and prices from these countries are higher. The Authority could not find any evidence of contraction of demand, change in pattern of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers. It is also noted that developments in technology have not been a cause for injury to the domestic industry.
- (v) In establishing that the material injury to the Domestic Industry has been caused by the imports from the subject countries, the Authority holds that the increase in market share of imports from the subject countries resulted in decline in the market share of the petitioner i.e. Domestic Industry and prevented the domestic industry from raising its market share, considering that the petitioner has set up new facilities for production of the subject goods. These imports have significantly depressed the prices of the domestic product forcing the Domestic Industry to sell at un-remunerative prices. The material injury to the Domestic Industry has, therefore, been caused by the dumped imports from the subject countries.

3. Landed Value

The landed value has been determined for the subject goods after adding to the weighted average c.i.f. price the applicable level of customs duties (except duties levied under Section 3, 3 (A), 8B, 9, 9(A) and 1% towards landing charges.

4. **Non-Injurious price**

While determining the non-injurious price for the like articles for the domestic industry, the Authority has used the actual cost of production of the subject goods to determine optimum cost of production for the domestic industry taking into account the normated best consumption norms and the actual price of the raw materials which are consumed for the production of the subject goods during the period of investigation. For calculation of injury margin, the authority compared the ex-factory non-injurious price determined for the period of investigations with the landed value of imported goods.

5. **Duty upto dumping margin:**

The Authority recommends the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry.

G. **INTEREST OF INDIAN INDUSTRY AND OTHER ISSUES**

- i) The Authority holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

- ii) The Authority also recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods.
- iii) The Authority notes that the imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from Russia, Ukraine & Korea in any way, and, therefore would not affect the availability of the product to the consumers.

H. CONCLUSIONS

It is seen, after considering the foregoing that:

- a) The subject goods originating in or exported from the subject countries have been exported to India below Normal Value, resulting in dumping.
- b) The Indian domestic industry has suffered injury. The domestic industry has suffered material injury in terms of subject goods produced by it. Further, establishment of the domestic industry is being materially retarded by the dumped imports, in as much as the domestic industry is trying to establish itself in the Indian market with new subject product.

- c) Injury has been caused by imports of subject goods from the subject countries.
- d) It is considered necessary to impose definitive anti-dumping duty on imports of subject goods originating in or exported from the subject countries.
- e) It is considered to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or lower so as to remove the injury to the domestic industry accrued on account of dumping. Accordingly, it is proposed that definitive anti-dumping duties equal to the difference between the amount of Column 9 of the Table below and the landed value of subject goods in \$/MT be imposed by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from subject countries under Chapter 84.55 of the Customs Tariff Act.

Sl. No	Sub-heading	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amt (USD/MT)	Unit measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	8455.30	Forged Rolls	Induction hardened Forged Rolls also known as Forged Cold Rolling Mills Rolls including work rolls and back up rolls (Sizes above 300 mm dia and up to 605 mm. Dia)	Korea RP	All	Any	Any	2851.91	Metric Tonne	USD
2.	8455.30	Forged Rolls	Induction Hardened Forged Rolls also known as Forged Cold Rolling Mills Rolls including work rolls and back up rolls (Sizes above 300 mm dia and up to 605 mm dia)	Any country except Ukraine and Russia	Korea RP	Any	Any	2851.91	Metric Tonne	USD

Sl. No	Sub-heading	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amt (USD/MT)	Unit measurement	Currency
3.	8455.30	Forged Rolls	Induction Hardened Forged Rolls also known as Forged Cold Rolling Mills Rolls including work rolls and back up rolls (Sizes above 300 mm dia and up to 605 mm dia)	Ukraine	All	Any	Any	2783.05	Metric Tonne	USD
4.	8455.30	Forged Rolls	Induction Hardened Forged Rolls also known as Forged Cold Rolling Mills Rolls including work rolls and back up rolls (Sizes above 300 mm dia and up to 605 mm dia)	Any country except Russia and Korea RP	Ukraine	Any	Any	2783.05	Metric Tonne	USD
5.	8455.30	Forged Rolls	Induction hardened Forged Rolls also known as Forged Cold Rolling Mills Rolls including work rolls and back up rolls (Sizes above 300 mm dia and upto 605 mm dia)	Russia	All	Any	Any	2762.79	Metric Tonne	USD
6.	8455.30	Forged Rolls	Induction Hardened Forged Rolls also known as Forged Cold Rolling Mills Rolls including work rolls and back up rolls (Sizes above 300 mm dia and up to 605 mm dia)	Any country except Korea RP and Ukraine	Russia	Any	Any	2762.79	Metric Tonne	USD

- f) Subject to the above, the Authority confirms the preliminary findings dated 11th December 2002.
- g) An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act, *supra*.

L.V. SAPTHARISHI, Designated Authority